



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

No. 61]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2005/फाल्गुन 13, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2005/PHALGUNA 13, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2005

अन्तिम जांच परिणाम—(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : यूरोपीय संघ (ई.यू.), संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्राक्सील एमाइन सल्फेट (एचएस) के आयातों संबंधी पाटनरोधी (मध्यावधि समीक्षा) जांच।

सं. 15/23/2004-डीजीएडो.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया:

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:-

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 1/3/2001 की अधिसूचना सं० 59/1/2001-डीजीएडो द्वारा अन्तिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया जिसमें ईयू सं.रा. अमरीका तथा जापान मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्राक्सील एमाइन सल्फेट (एचएस) के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।

- ii) इस कार्रवाई में मूल जांच दिनांक 3.3.2000 को आरंभ की गई थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच-परिणामों को दिनांक 4.8.2000 की अधिसूचना संख्या 59/1/2001-डीजीएडी द्वारा जारी किया गया । प्राधिकारी के अन्तिम जांच-परिणामों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 1.3.2001 की अधिसूचना सं० 59/1/2001-डीजीएडी द्वारा जारी किया गया और संबद्ध माल पर अन्तिम शुल्क दिनांक 28.3.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 31/2001-सीमाशुल्क द्वारा लगाया गया था ।
- iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (यथासंशोधित) और उसके तहत बनाई गई सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन तथा संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 में प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करें ।
- iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी को बदली हुई परिस्थितियों में संबद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा किए जाने के संबंध में यूरोपीय संघ से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ । उपर्युक्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक जानकारी के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचार किया कि इस समय लागू पाटनरोधी शुल्कों की मध्यावधि समीक्षा करना प्राधिकारी के ध्यान में लाई गई बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर यथोचित रहेगा । तदनुसार, दिनांक 14 सितंबर, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई और इसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार उपर्युक्त संबद्ध देशों के विरुद्ध लागू शुल्क के संबंध में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के तहत पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच आरंभ की गई ताकि इस बात का निर्धारण हो जाए कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए अपेक्षित लगाए गए शुल्क को जारी रखा जाए और यह भी कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने अथवा उसमें कमी या बढ़ोतरी करने अथवा दोनों को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप क्षति जारी रह सकेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।
- v) इन अंतिम जांच-परिणामों की समीक्षा किए जाने संबंधी निर्णय के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 14 सितंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 15/23/2004-डीजीएडी द्वारा मौजूदा जांच इस आशय से आरंभ की ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन तथा संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद पाटनरोधी नियमावली कहा गया

है) के अनुसार ई.यू., सं.रा.अमरीका तथा जापान (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से आयातित हाइड्राक्सील एमाइन सल्फेट पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके। इस समीक्षा में दिनांक 1.3.2001 की अधिसूचना सं० 59/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलुओं को कवर किया गया है।

vi) प्राधिकारी ने यह समीक्षा आरंभ किए जाने के बाद नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को जांच-आरंभ अधिसूचना सहित प्रश्नावलियाँ भेजी ताकि संगत जानकारी प्राप्त की जा सके:-

1. एलाइड सिगनल इन्क.
101, कोलम्बिया रोड,
पो.ओ.नं० 1039, सोलवे 3,
मोरिसटारून
न्यू जर्सी 079621039, यूएसए
2. बीएसएसएफ- जर्मनी,
जोसेफ रिट्ज हुगो फाक्यूस,
बीएसएसएफ एक्टिंग्यूलसेहाफ्ट,
लुडविगसेफेन, जर्मनी
3. डीएसएम
पो.ओ. बाक्स 6500
6401 जेएच हेरेलन, दि नीदरलैंड्स
4. यूबीई इन्ड. लि०
यूबीई बिल्डिंग
2-3-11 हिगाशी
शिंगावा, टोक्यो-140-8633
जापान
5. टोआगोसेई कं० लि०,
14-1, निशि-शिम्याशी, I कोम,
मिनाटो-कु,
टोक्यो-105, जापान

6. यूबीई इंडस्ट्रीज
3/11, हिंगाशी-शिंगावा
2 कोल शिंगावा कु
टोकयो-140, जापान
 7. मै0 बीएसएफ एक्टिंगेसलस्काफ्ट
सीएआरएल-बीओएससीएच-एसटीआरएबीई, 38
67056, लुडविगसचाफेन,
जर्मनी
 8. मै0 रोन पाउलेंस सा (एवंटिस)
क्यूवड पॉल डाउमर, एफ-92408,
कोरबेवोई सेडेक्स
फ्रांस
 9. मै0 बीएसएफ साउथ ईस्ट एशिया, पीटीई, लि0,
7, टेमासेक बाउलवर्ड,
35-01, सनटेक टॉवर वन,
सिंगापुर-038987
 10. एवेंटिस एनिमल न्यूट्रिशन एशिया पैसिफिक, पीटीई लि0,
1, लोयांग वे 4, सिंगापुर-507028
 11. मै0 बीएसएफ (थाई) लि0,
23 वीं मंजिल, एम्पोरियम टॉवर,
622, सुखुमविल रोड,
क्लांगटन, क्लांगटोए,
बैंकाक-10110, थाइलैंड
 12. मै0 बीएसएफ कार्पोरेशन
केमिकल डिविजन,
वाशिंगटॉसाइट,
प्लीजंटव्यूज एंड पेरिसिंग, वाशिंगटन, एनजे 07882
- vii) उक्त नियमावली के अनुसार संगत जानकारी मंगाने के लिए भारत के घरेलू उद्योग को भी सूचनाएं भेजी गईं ।

viii) नियम 6(2) के अनुसार, जांच-प्रारंभ किए जाने के संबंध में संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को भी सूचित किया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दिए जाने के संबंध में अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दे दें ।

ix) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मंगाए जाने हेतु भारत में संबद्ध माल के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों तथा उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई:-

1. मै0 ग्लेक्सो इंडिया लि0, मुंबई
2. मै0 सिरिस लि0, हैदराबाद
3. मै0 शासुन केमिकल्स एंड ड्रग्स लि0, चेन्नई
4. मै0 अरबिंदो फार्मा लि0, हैदराबाद
5. मै0 केमिनोर ड्रग्स लि0, हैदराबाद
6. मै0 गोदावरी ड्रग्स लि0, सिकन्दराबाद
7. मै0 विर्चो लेबोरेट्रीज लि0,
8. मै0 एसओएल फार्मास्यूटिकल्स लि0, हैदराबाद
9. मै0 हेरेन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स , हैदराबाद
10. मै0 हसमुख रे एंड कं0, मुंबई
11. मै0 अरिहन्त इम्पैक्स, मुंबई
12. मै0 बीएसएसएफ इंडिया लि0, मुंबई
13. मै0 प्रिया इंटरनेशनल, मुंबई
14. मै0 यूआरएमआई केमिकल्स, मुंबई
15. मै0 मनाली केमिकल्स, मुंबई
16. मै0 इंडियन ड्रग्स मैनुफै. आसन., मुंबई
17. मै0 फ्रागरांस एंड फ्लेबर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएफएआई), मुंबई
18. मै0 रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया, केरल
19. मै0 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), मुंबई
20. मै0 इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन (आईपीए), मुंबई
21. मै0 दीपक निट्राइट लि0, नंदेसरी
22. डेलीगेशन ऑफ यूरोपियन कमीशन टू इंडिया, नई दिल्ली
23. मै0 बीएसएसएफ इंडिया लि0, नई दिल्ली
24. मै0 केमोक्स लेबोरेट्रीज लि0, मुंबई
25. मै0 एलाइड सिगनल इंडिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली
26. मै0 इंडियन केमिकल मैनु. एसो., नई दिल्ली

27. मै0 आर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल्स प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, मुंबई
 28. मै0 बल्क ड्रग्स मैन्फ़. एसो. (बीडीएमए), हैदराबाद
 29. मै0 पेस्टिसाइड्स एसो. ऑफ इंडिया (पीएआई), नई दिल्ली
- x) दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक (12 महीनों) की जांच अवधि के लिए जांच की गई। किंतु, क्षति विश्लेषण अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001, अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002, अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003 के वर्षों और जांच अवधि के संबंध में किया गया।
 - xi) वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) से अनुरोध किया गया कि वे पिछले तीन वर्षों और जांच-अवधि के लिए संबद्ध माल के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।
 - xii) जांच आरंभ अधिसूचना की प्रतिलिपियां व्यापक परिचालन के लिए फिक्की, सीआईआई और एसोचैम को भी भेजी गई।
 - xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को सभी इच्छुक पक्षकारों को अनुरोध पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई।
 - xiv) संबद्ध माल के घरेलू उत्पादक और मूल जांच में मूल याचिकाकर्ता मै0 दीपक निट्राइट लि0 ने इस समीक्षा का विरोध करते हुए अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।
 - xv) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा यथासंभव प्रस्तुत जानकारी की पड़ताल की और हुई क्षति की जांच की ताकि सामान्यतया स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर भारत में संबद्ध माल की अनुकूलतम उत्पादन लागत तथा उत्पादन तथा बिक्री लागत की गणना की जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाना उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रहेगा।
 - xvi) प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकारों की मौखिक रूप से सुनवाई करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 22 दिसंबर, 2004 को सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि, यूरोपीय संघ के संबद्ध माल के आवेदक/निर्यातक तथा अन्य इच्छुक पक्षकार उपस्थित हुए। इस सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि उन्होंने जो भी विचार मौखिक रूप से व्यक्त

किए, उन्हें लिखित रूप से दर्ज कराएं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त लिखित निवेदनों पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया।

- xvii) प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को सभी इच्छुक पक्षकारों को अनुरोध पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई।
- xviii) विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा जांच आरंभ अधिसूचना के प्रत्युत्तर और सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् व्यक्त विचारों की चर्चा आगे संगत पैराग्राफों में इस सीमा तक की गई है जितना कि वह नियमावली के अनुसार हो और इस मामले में उनका जितना संबंध हो।
- xix) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, ज्ञात इच्छुक पक्षकारों को इन जांच-परिणामों में विचार किए गए आवश्यक तथ्यों/आधार का खुलासा दिनांक 2 जनवरी, 2005 को किया गया और इस संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर इन जांच परिणामों में विचार किया गया है।
- xx) इस अधिसूचना में **** एक इच्छुक पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के तहत विचार किया गया।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

2. मूल जांच तथा मौजूदा समीक्षा में शामिल उत्पाद हाइड्राक्सील एमाइन सल्फेट (एचएएस) है जो उपर्युक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के शीर्षक संख्या 2825.1003 और आईटीसीएचएस वर्गीकरण के तहत आता है। किंतु, यह वर्गीकरण केवल इंगितात्मक है और इसकी मौजूदा जांच के दायरे में कोई बाध्यता नहीं है। चूंकि यह बदली हुई परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा जांच है, इसलिए मूल जांच में कवर किए गए उत्पाद को इस जांच में कवर किया गया है। विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के तहत आने वाले उत्पाद के मुद्दे के संबंध में किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा कोई दलील नहीं दी गई है, अतः प्राधिकारी का निर्णय है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और संबद्ध देशों द्वारा विनिर्मित तथा निर्यातित उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं।

ग. घरेलू उद्योग

3. मूल जांच में घरेलू उद्योग की ओर से मै0 दीपक निट्राइट लि0 द्वारा दायर पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन-पत्र शामिल किया गया था । वे भारत में संबद्ध माल के प्रमुख उत्पादक थे और पाटनरोधी नियमावली के तहत याचिका दायर करने के लिए उनकी स्थिति थी । इस मध्यावधि समीक्षा में मै0 दीपक निट्राइट लि0 भारत में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है, अतः संबद्ध माल के कुल उत्पादन में उनका प्रमुख हिस्सा है और वही पाटनरोधी नियमावली के आशय के भीतर घरेलू उद्योग है ।

घ. समीक्षा का आरंभ और उठाए गए तर्क

घ.1 आवेदकों के विचार

4. आवेदक के विचारों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

- i) आवेदक ने निवेदन किया है कि पाटनरोधी शुल्कों के लगाए जाने के बाद सल्फामेथोक्साजोल के पुनर्निर्यात के वास्ते अग्रिम लाइसेंस के तहत मै0 बीएएसएफ द्वारा किए गए निर्यात को छोड़कर, संबद्ध माल की प्रत्यक्ष बिक्रियां नहीं हुई हैं । किंतु, यदि संबद्ध माल की प्रत्यक्ष बिक्री हुई भी होती तो भी पाटन मार्जिन न्यूनतम रहता क्योंकि कारखानागत घरेलू बिक्री कीमत ***** यूरो/कि.ग्रा बैठती है और कारखानागत निर्यात कीमत ***** यूरो/कि.ग्रा बैठती है । उपर्युक्त निर्यात कीमत तथा सामान्य कीमत के आधार पर ईयू से निर्यातित संबद्ध माल का पाटन मार्जिन नगण्य है ।
- ii) इस आवेदक ने यह तर्क दिया है कि मूल जांच में पाटनरोधी उपायों के फलस्वरूप कुल मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कोई सुधार नहीं हुआ है । आगे यह भी निवेदन है कि पाटनरोधी शुल्क वाले संबद्ध माल के स्थान पर मुख्य रूप से बेलारूस जैसे अन्य स्रोतों से पाटित आयातों को रखा गया है । घरेलू उद्योग इसके स्थान पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद अपनी बाजार स्थिति में सुधार नहीं कर पाया है जिससे यह परिलक्षित होता है कि यह क्षति ई.यू. से किए गए निर्यात के कारण बिल्कुल भी नहीं हुई है ।
- iii) आवेदक ने निवेदन किया है कि एचएस की घरेलू मांग में गिरावट पाटनरोधी उपायों को लागू करने के फलस्वरूप आई है । उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि चीन के निर्यातकों से गहन प्रतिस्पर्धा की वजह से अन्तिम उत्पाद अर्थात् सल्फामेथोक्साजोल की कीमतों में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप

एचएस के भारतीय घरेलू प्रयोक्ता चीन के एंटीबायोटिक उत्पादों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। मांग में इस गिरावट के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- iv) घरेलू उद्योग ने वर्ष 2002 में सोडियम निट्राइट तथा तथा सोडियम नाइट्रो एरोमेटिक्स के अपने मौजूदा दोनों प्रभागों का समेकन किया है। इन दोनों प्रभागों के समेकन के फलस्वरूप संबद्ध माल के उत्पादन तथा लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- v) उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक ने निवेदन किया है कि ई.यू. से संबद्ध माल के निर्यात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है क्योंकि यह क्षति पाटनरोधी उपायों के बावजूद बनी रही है। वास्तव में, ई.यू. से होने वाले निर्यात उन स्रोतों के सान पर रखे गए हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है और मांग में कमी होने के कारण घरेलू उद्योग पाटनरोधी उपायों के बावजूद भी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं कर सका है।
- vi) किंतु, समीक्षा जांच आरंभ किए जाने के पश्चात् आवेदक पाटन, यदि कोई हो की मात्रा तथा सीमा के निर्धारण के लिए अपेक्षित प्रश्नावली प्रत्युत्तर दर्ज कराने में असफल रहा है। इसके पश्चात् यूरोपीय आयोग ने, जिनकी मार्फत समीक्षा संबंधी आवेदन-पत्र दायर कराया गया था, अपना प्रथम आधार वापस ले लिया जिस पर समीक्षा के लिए आवेदन किया गया था अर्थात् यूरोपीय संघ से कोई पाटन नहीं हुआ। उन्होंने तर्क दिया है कि समीक्षा संबंधी उनका अनुरोध क्षति के उनके एकमात्र दावे पर आधारित है और पाटन संबंधी पहलू को ई.यू. के समीक्षा अनुरोध के कानूनी अनुपालन में किसी पूर्वाग्रह के वापस लिया जा सकता था। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि पुनरीक्षा अनुरोध में पाटन-जांच के अभाव में क्षति संबंधी परिणाम अभी भी देय रहेगा और नकारात्मक जांच परिणाम के फलस्वरूप इन उपायों को समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा करना डब्ल्यूटीओ नियमावली के तहत आवश्यक है। उन्होंने निवेदन किया है कि पाटन तथा क्षति निर्धारण परस्पर आश्रित कारक नहीं होते हैं और पाटन होने पर भी शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता है बशर्ते कि यह पाया जाता है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई हो। अतः उन्होंने तर्क दिया है कि क्षति संबंधी जांच के लिए पाटन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आवेदक का दायित्व नहीं बनता है जिसे वास्तविक क्षति पर ध्यान दिया जाना हो जो उनके विचार से ई.सी. के निर्यातकों द्वारा ली गई किसी भी कीमत के होते हुए भी बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण मौजूद नहीं है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग के विचारों को संक्षिप्त रूप में नीचे दिया गया है:

- i) घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न निवेदनों में समीक्षा जांच आरंभ किए जाने का विरोध किया है और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया है कि भारतीय कानून के अनुसार कोई भी समीक्षा पाटन तथा क्षति दोनों पर लागू होगी, इस प्रकार भारतीय कानून में पाटन अथवा क्षति की आंशिक समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- ii) घरेलू उद्योग ने आगे यह भी तर्क दिया है कि जांच आरंभ करने से पहले समीक्षा के संबंध में आवेदक द्वारा कतिपय जानकारी देना आवश्यक होता है जोकि आवेदक ने प्रस्तुत नहीं की है, अतः माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वह मध्यावधि समीक्षा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आरंभ करें।
- iii) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि समीक्षा के लिए आवेदन यूरोपीय संघ द्वारा यूरोपीय निर्यातकों की ओर से दिया गया है जबकि जांच आरंभ अधिसूचना में यह कहा गया है कि ई.यू. के एक निर्यातक अर्थात् मै0 बीएएसएफ लि0, जर्मनी ने एक अनुरोध पाटनरोधी शुल्क की बदली हुई परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा के लिए दायर की है।
- iv) घरेलू उद्योग ने आगे यह भी तर्क दिया है कि समीक्षा के लिए आवेदक निर्धारित प्रारूप तथा तरीके में समीक्षा आरंभ होने के बाद भी जानकारी प्रदान करने में असफल रहा है। उनका तर्क है कि चूंकि सामान्य मूल्य तथा निर्यातक कीमतों संबंधी जानकारी आवेदक के पास उपलब्ध है फिर भी, उनकी आधारिक जिम्मेदारी यह है कि वे इस जानकारी को निर्धारित प्रारूप तथा तरीके में प्रदान करें और उनके दावे के समर्थन में प्रमाण का दायित्व आवेदक पर निर्भर है।
- v) घरेलू उद्योग के विचार में उत्पादन लागत तथा सामान्य मूल्य संबंधी जानकारी निर्यातक के पूर्णतया क्षेत्राधिकार में होता है। इस तथ्य को रोकते हुए निर्यातक समीक्षा की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा है और वह अपनी सर्वोत्तम सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर रहा है। अतः, निर्यातक से पहले यह अपेक्षा है कि वह कानून तथा वास्तविक न्याय द्वारा अपने ऊपर दायित्व समझे। संपूर्ण साक्ष्य के अभाव में समीक्षा आरंभ नहीं की जानी चाहिए थी जिसमें आवेदक निर्यातक द्वारा किसी पाटन के दावे को पुख्ता किया जाता हो और घरेलू उद्योग को कोई

क्षति नहीं हुई हो और दावे के समर्थन को प्रमाणित करने संबंधी साक्ष्य का भार क्षति का साक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रतिवादी घरेलू उद्योग पर मढ़ने से पहले सबसे पहले आवेदक के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने आगे यह भी दलील दी है कि कानून के अनुसार पाटन तथा क्षति की जांच करना किसी समीक्षा में अलग-अलग नहीं किया जा सकता है और यह निर्धारित करने के लिए दोनों की साथ-साथ जांच की जानी चाहिए कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने अथवा उसमें कमीबेशी किए जाने की स्थिति में पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. प्राधिकारी ने यूरोपीय आयोग के उन तर्कों को नोट किया है कि बदली हुई परिस्थितियों में समीक्षा में पाटन तथा क्षति संबंधी निर्धारण दो अलग-अलग बातें हैं और इसके लिए दो अलग-अलग जांच की जा सकती है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पाटन तथा क्षति के नहीं होने के आधार पर कोई अनुरोध करना यूरोपीय निर्यातकों तथा इसी के ऊपर निर्भर है कि वे इन दोनों बातों पर अपने-अपने दावे पुख्ता करें। इसी ने भी यह दावा किया कि जांच अवधि के दौरान पाटन का होना अथवा नहीं होते रहने का क्षति संबंधी जांच से कोई संबंध नहीं है जोकि इस उद्योग के मौजूदा दर्जे के आधार पर अलग से जांच हो सकती है।
7. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित धारा 9क(5) में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने को जारी रखने की आवश्यकता पर समय-समय पर समीक्षा करेगा और उसे प्राप्त जानकारी के आधार पर यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे शुल्क लगाए जाने को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह इसे वापस लिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा।
8. कशर के अनुच्छेद 11.21 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी लगाए गए शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की उस स्थिति में समीक्षा करेगा जबकि ऐसा करना उनकी पहल पर आवश्यक समझा जाता हो बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद एक यथोचित समयावधि समाप्त हो गई हो। ऐसे किसी भी इच्छुक पक्षकार के अनुरोध पर किया जा सकेगा जो इस प्रकार की समीक्षा की आवश्यकता को साबित करने के लिए सकारात्मक जानकारी प्रदान करेगा। इच्छुक पक्षकारों को प्राधिकारी से यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि वह इस बात की जांच करें कि क्या पाटन को समाप्त

करने के लिए लगाए गए शुल्क को जारी रखना, क्या ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने अथवा उसमें कमी बेशी करने अथवा दोनों ही बातें होने पर क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस पैराग्राफ के तहत समीक्षा के परिणामस्वरूप यदि प्राधिकारी यह निर्धारित कर ले कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखना अब जरूरी नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह ऐसे शुल्क को तत्काल समाप्त कर सकेगा।

9. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्यातक द्वारा कोई पाटन नहीं होने और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होने संबंधी दावों को प्रमाणित करते हुए पूर्ण साक्ष्य के अभाव में यह समीक्षा आरंभ नहीं की जानी चाहिए थी और कोई पाटन नहीं होने के दावे को प्रमाणित करने संबंधी साक्ष्य का भार पूर्णतया सबसे पहले आवेदक के ऊपर होता है, इससे पहले कि क्षति का साक्ष्य प्रदान करने संबंधी प्रतिवादी घरेलू उद्योग के ऊपर यह डाला जाए। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि कानून के अनुसार पाटन तथा क्षति संबंधी जांच किसी समीक्षा में अलग-अलग नहीं की जा सकती है और दोनों की जांच यह निर्धारित करने के लिए साथ-साथ की जानी चाहिए कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने अथवा उसमें कमी बेशी किए जाने की स्थिति में पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति होने के संभावना है।
10. इस समीक्षा के पक्षधर आवेदकों ने तर्क दिया है कि पाटन तथा क्षति का निर्धारण परस्पर आश्रित नहीं होते हैं और पाटन की मौजूदगी की स्थिति में लगाए गए शुल्क को रद्द किए जाने की आवश्यकता है बशर्ते प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। अतः, पाटन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवेदक का दायित्व क्षति संबंधी जांच करने के मामले में संबंधित नहीं है जोकि वास्तविक क्षति के संबंध में मूल रूप से केन्द्रित होता है।
11. प्राधिकारी ने इन तर्कों की जांच की है और उसका विचार है कि नियम 23 में 'संतुष्टि' की स्थिति सही-सही जांच करने के पश्चात लगाए गए शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की प्राधिकारी की संतुष्टि से संबंधित है न कि समीक्षा आरंभ करने के लिए। कोई समीक्षा आरंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि प्राधिकारी के पास सकारात्मक जानकारी उपलब्ध हो जिसके आधार पर प्राधिकारी यह निर्णय करने के लिए विश्वास कर ले कि क्या लगाए गए शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता संबंधी जांच करना आवश्यक है। मौजूदा मामले में आवेदक ने प्राधिकारी के समक्ष अपने समीक्षा आवेदन-पत्र में सकारात्मक जानकारी दर्ज कराई थी और इस प्रकार दर्ज सकारात्मक जानकारी के आधार

पर समीक्षा आरंभ की गई । दावों के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करना और विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रति दावे करना जांच का विषय है और इसे उन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है जिनमें जांच के दौरान समीक्षा हेतु अनुरोध करने वाला पक्षकार शामिल होता है । किंतु, इस समीक्षा का निष्कर्ष समीक्षा के लिए विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की क्वालिटी पर निर्भर करेगा । अतः, प्राधिकारी का विचार है कि उसके पास उपलब्ध सकारात्मक जानकारी के आधार पर समीक्षा ठीक से आरंभ की गई है जिसमें यह सुझाव दिया गया कि लागू शुल्क संबंधी समीक्षा करना आवश्यक है ।

12. किंतु, पाटन तथा क्षति संबंधी जांच को अलग-अलग किए जाने के मुद्दे के संबंध में जहां तक कोई पाटन नहीं होने के दावे के प्रमाण में साक्ष्य के भार का संबंध है, आवेदक के तर्कों की जांच करार के अनुच्छेद 11.2, अनुच्छेद 11.3 तथा अनुच्छेद 3.4 के संदर्भ में की गई है । अनुच्छेद 11.3 में यह उपबंध है कि किसी समीक्षा के परिणामस्वरूप निश्चयात्मक शुल्क को अगले 5 वर्षों की समयावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा बशर्ते उस समीक्षा में पाटन तथा क्षति दोनों को कवर किया गया हो । इसके प्रभाव से पाटन अथवा क्षति को कवर करते हुए आंशिक समीक्षा अथवा दोनों को कवर करते हुए विस्तृत समीक्षा किए जाने का प्रावधान है । किंतु, प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल क्षति को कवर करते हुए समीक्षा में पाटन की मात्रा तथा सीमा को पूर्णरूप से अनदेखी की जा सकती है ।
13. करार के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के कारकों की जांच पाटित आयातों के संदर्भ में की जा सकेगी । अनुच्छेद 3.1 में यह उपबंध है कि -

" गाट 1994 के अनुच्छेद vi के प्रयोजनार्थ क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होगा और उसमें इन दोनों की उद्देश्यपूर्ण जांच शामिल होगी (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार की कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का प्रणामी प्रभाव ।"

इसके अलावा, अनुच्छेद 3.4 में यह उपबंध है कि " संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों तथा सूचियों का मूल्यांकन शामिल होगा जिनका उद्योग की स्थिति पर संबंध होता है, जिसमें बिक्रियों, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, पूंजी निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू उद्योग पर बुरा प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा में वास्तविक तथा संभाव्य गिरावट शामिल होती है"

14. अतः प्रावधान के उपरोक्त उपबंधों से ऐसा प्रतीत होता है कि पाटनरोधी जांच के संदर्भ में घरेलू उद्योग की दशा की जांच में पाटन तथा पाटन की मात्रा, मात्रा तथा मार्जिन, दोनों ही दृष्टियों से प्रत्यक्ष प्रभाव को शामिल किया जाना है ।
15. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 में यह व्यवस्था है कि यदि अनुच्छेद 11.2 के स्पष्ट उपबंधों को दो भागों में विभाजित किया जाता है जैसाकि ईसी द्वारा व्याख्या की गई है, ऐसी स्थिति में इस उपबंध के दूसरे वाक्य में यह प्रावधान है कि संबंधित पक्षकार समीक्षा किए जाने के लिए कहा सकता है और प्राधिकारी इस बात की जांच करेगा कि " यदि शुल्क को समाप्त किया जाए अथवा उसमें कमी बेशी की जाए तो ऐसी स्थिति में क्या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । " इस प्रावधान में प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह मौजूदा जांच, यदि कोई हो, की जांच करे और यह भी जांच करे कि क्या इन शुल्कों को समाप्त किए जाने के बाद क्षति की पुनरावृत्ति होगी । इस उपबंध के दूसरे भाग पर विचार करते समय पाटन की सीमा इस बात का निर्धारण करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होगा कि क्या शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी, बेशक उपलब्ध शुल्क संरक्षण के कारण कोई क्षति नहीं होती हो ।
16. करार के उपर्युक्त सभी उपबंधों से स्पष्ट है कि यदि यह तय करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच करने के लिए आंशिक समीक्षा अपेक्षित है कि क्या प्रभावी पाटन-जांच द्वारा शुल्क को जारी रखना जांच का एक अभिन्न हिस्सा बनता है और पाटन की मौजूदा स्थिति और घरेलू उद्योग के मौजूदा स्तर के अलावा, जबकि ऐसी समीक्षा में यह जांच की जानी चाहिए कि क्या क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है । अतः ईसी का यह मानना कि बदली हुई परिस्थितियों में समीक्षा के तहत क्षति की जांच करना, जांच में केवल एकमात्र विषय है और इसे, इस तथ्य के बावजूद की जा सकती है कि क्या पाटन जारी रहता है अथवा नहीं, यथोचित प्रतीत नहीं होता है ।
17. ईसी ने यह भी निवेदन किया है कि पाटन की जांच उनके समीक्षा संबंधी अनुरोध से हटा दी जा सकती है और इसमें ईसी के समीक्षा अनुरोध के कानूनी अनुपालन में कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा । इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक जानकारी पर आधारित समीक्षा यदि एक बार आरंभ की जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक पक्षकारों का यह दायित्व होता है कि वे विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपने-अपने दावे तथा प्रतिदावे प्रस्तुत कर दें जिनमें पाटन तथा क्षति के विषय शामिल हों । यदि ईसी

कोई पाटन नहीं होने के अपने दावे को वापस लेना चाहता है और घरेलू उद्योग ईयू उत्पादकों द्वारा किए गए पाटन का साक्ष्य प्रस्तुत करना है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि वह पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के अनुसार सर्वोत्तम तथ्य अनुच्छेद के तहत जांच करे।

18. प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि जांच के दौरान यूरोपीय आयोग ने उनके द्वारा दायर प्रारंभिक याचिका के अलावा अतिरिक्त निवेदन दायर किया है। इस संबंध में प्राधिकारी यह उल्लेख करना चाहेगा कि घरेलू उद्योग द्वारा उस सार्वजनिक फाइल की जांच की गई है जिसमें जांच के दौरान इच्छुक पक्षकारों द्वारा दायर अगोपनीय निवेदन शामिल हैं।

पाटन मार्जिन की गणना - पद्धति

ड. पाटन का निर्धारण: सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य तथा पाटन मार्जिन

ड.1 यूरोपीय संघ

सामान्य मूल्य

19. प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी। ईयू के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित प्रारूप तथा तरीके में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निवेदन दर्ज नहीं कराया है।
20. यूरोपीय आयोग ने निवेदन किया है कि कोई पाटन नहीं होने का उनका दावा वापस ले लिया गया माना जाए और प्राधिकारी को चाहिए कि वह इस बात के होते हुए भी केवल क्षति संबंधी पहलू की जांच करे कि क्या पाटन जारी है अथवा नहीं। पिछले भाग में यह बताया गया है कि शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी संभावना की आंशिक समीक्षा किए जाने पर पाटन की सीमा का आंकलन करना निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि आवेदक ने इस कार्रवाई में कानून द्वारा यथा अपेक्षानुसार सहयोग नहीं किया है और उन्होंने अपने सामान्य मूल्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं देने की बात का सहारा लेते हुए बड़े आराम से और क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में कोई साक्ष्य दिए बिना सीमित तर्क प्रस्तुत किए हैं। यह कानून तथा स्थापित न्यायशास्त्र के विरुद्ध है।

अतः किसी अन्य जानकारी के अभाव में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मौजूदा पाटन की सीमा के आंकलन के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का आधार माना गया है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उन्होंने ईयू की मौजूदा घरेलू कीमतों का साक्ष्य प्राप्त करने का सर्वोत्तम प्रयास किया है किंतु जांच अवधि के लिए कीमतों संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी।

21. करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई पक्षकार पहुंच बनाने के लिए इंकार करता है अथवा वह यथोचित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में बहुत बाधा डालता है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक तथा अन्तिम निर्धारण, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जा सकते हैं। करार के अनुबंध 2 में आगे यह भी व्यवस्था है कि ऐसी निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया जा सकता है। चूंकि ईयू के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित जानकारी दर्ज नहीं कराई है अतः सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। अतः ईयू के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण **** अम.डा./कि.ग्रा. किया गया है।

निर्यात कीमत

22. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार, ईयू ने जांच अवधि के दौरान 764 मी.टन. एचएएच का निर्यात किया है। कारखानागत निर्यात कीमत के निर्णय के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजनों पर विचार किया गया है। ईयू के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में कारखानागत निर्यात कीमत **** अम.डा./कि.ग्रा. निर्धारित की गई है।

ड.2 सं.रा. अमरीका

सामान्य कीमत

23. प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी। सं.रा. अमरीका के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने

प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित प्रारूप तथा तरीके में निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई इच्छुक पक्षकार पहुंच बनाने से मनाही करता है अथवा एक यथोचित समायोधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अधिक बाधा पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक अथवा अन्तिम निर्धारण, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जा सकेगा। करार के अनुबंध 2 में आगे यह भी व्यवस्था है कि ऐसा निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया जा सकेगा। चूंकि अमरीका के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपना-अपना निवेदन दर्ज नहीं कराया है अतः सभी निर्यातकों/उत्पादकों संबंध में सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। किसी अन्य जानकारी के अभाव में, मौजूदा पाटन की सीमा के आंकलन के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उन्होंने ईयू में प्रचलित घरेलू कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने का सर्वोत्तम प्रयास किया है किंतु वे जांच अवधि के लिए कीमत आंकड़े प्राप्त नहीं कर सके। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण संयुक्त राज्य अमरीका के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में **** अम.डा./कि.ग्रा. किया गया है।

निर्यात कीमत

24. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान किए गए आयात आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार सं.रा. अमरीका ने जांच अवधि के दौरान 1108 मी.टन एचएस का निर्यात किया है। कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजनों पर विचार किया गया है। कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण सं.रा. अमरीका के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में **** अम.डा./कि.ग्रा. किया गया है।

ड.3 जापान

सामान्य मूल्य

25. प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी। जापान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा

अपेक्षित प्रारूप तथा तरीके में निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई इच्छुक पक्षकार पहुंच बनाने से मनाही करता है अथवा एक यथोचित समाधावधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अधिक बाधा पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक अथवा अन्तिम निर्धारण, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जा सकेगा। करार के अनुबंध 2 में आगे यह भी व्यवस्था है कि ऐसा निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया जा सकेगा। चूंकि जापान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपना-अपना निवेदन दर्ज नहीं कराया है अतः सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। किसी अन्य जानकारी के अभाव में, मौजूदा पाटन की सीमा के आंकलन के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उन्होंने ईयू में प्रचलित घरेलू कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने का सर्वोत्तम प्रयास किया है किंतु वे जांच अवधि के लिए कीमत आंकड़े प्राप्त नहीं कर सके। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में **** अम.डा./कि.ग्रा. किया गया है।

निर्यात कीमत

26. प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि जापान के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण नकारात्मक किया जाता है क्योंकि डीजीसीआईएंडएस द्वारा गलत आयात सौदे बताए गए हैं। प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता से प्राप्त सौदे-वार आंकड़ों की जांच की है और उसी पर जापान के निर्यातकों/उत्पादकों की ओर से किए गए असहयोग के कारण भारित औसत निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार जापान ने जांच अवधि के दौरान 704 मी.टन. एचएस का निर्यात किया। कारखानागत निर्यात कीमत के निर्णयन के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजनों पर विचार किया गया है। कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण जापान के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में **** अम.डा./कि.ग्रा. किया गया है। जापान के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में निर्धारित सामान्य कीमत तथा निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन नकारात्मक पाया गया है क्योंकि जांच अवधि के दौरान निर्यात कीमत सामान्य मूल्य की तुलना में अधिक रही। अतः जापान को इस जांच में शामिल संबद्ध देशों की सूची से हटा दिया गया है और उनकी

आयात मात्रा को क्षति की जांच के प्रयोजनार्थ पाटित आयातों से अलग कर दिया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर जापान को इस जांच के संबद्ध देशों से हटा दिया गया है। इसके पश्चात् इस जांच में जहां कहीं हवाला दिया गया है, संबद्ध देश केवल ईसी तथा संयुक्त राज्य अमरीका ही रहेंगे।

पाटन मार्जिन

27. यह नोट किया जाता है कि टंकण की गलती के कारण प्रकटन विवरण-पत्र में पाटन मार्जिन% गलती से टंकित किया गया जिसे अब सही कर दिया गया है। ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया:-

संबद्ध देश	सामान्य मूल्य(अम.डा./मी.टन)	निर्यात कीमत (\$ मी.टन)	पाटन मार्जिन(%)
ईसी	*****	*****	*****
यूएसए	*****	*****	*****
जापान	*****	*****	*****

28. उपरोक्त को देखते हुए जापान को इस जांच में शामिल देशों में से हटा दिया गया है। इसे बाद इस जांच में जहां कहीं हवाला दिया गया है संबद्ध देश केवल ईसी तथा संयुक्त राज्य अमरीका ही रहेंगे। संबद्ध देशों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण काफी पाया गया है।

क्षति निर्धारण की पद्धति और कारणात्मक संबंध की जांच

च. क्षति का निर्धारण

च.1 क्षति का संचयी आंकलन

29. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(iii) के अनुसार जिन मामलों में कोई उत्पाद एक से अधिक देशों से साथ-साथ आयात किया जा रहा हो और उसका संबंध पाटनरोधी जांच के अंतर्गत साथ-साथ हो, ऐसे मामलों में प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह ऐसे आयातों के प्रभाव का आंकलन संचयी आधार पर करे, उसका निर्धारण तब किया जाए कि (क) प्रत्येक देश से होने वाले आयात के संबंध में साबित पाटन मार्जिन, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2%

से अधिक हो और प्रत्येक देश से होने वाले आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3% हो, और (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के मद्देनजर यथोचित हो। प्राधिकारी ने पाया है कि प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन 2% से अधिक है। इन संबद्ध देशों से आयात मात्रा सामूहिक रूप से 45.82% है और यह अलग-अलग देश के मामले में कुल आयात के 3% से भी अधिक है।

30. जानकारी की जांच के बाद प्राधिकारी ने पाया कि संबद्ध देशों से आने वाले इस संबद्ध माल का आयात उसी टैरिफ वर्गीकरण के तहत किया गया है। आयातित उत्पाद का प्रयोक्ता उद्योग और घरेलू उद्योग एक ही है। प्रयोक्ताओं द्वारा विभिन्न देशों से एक ही उत्पाद मंगाया गया है और उसका प्रयोग अलग-अलग तरह से हुआ है। आयात का माध्यम भी एक ही पाया गया है। अतः प्राधिकारी ने यह यथोचित पाया कि आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों और आयातित उत्पाद तथा समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के मद्देनजर घरेलू उत्पादित समान उत्पाद पर संबद्ध माल के आयात के प्रभाव का संचयी आंकलन किया जाए। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयात द्वारा हुई क्षति के संचयी प्रभाव की जांच करना उचित समझा।

च.2 क्षति का जारी रहना

च.2.1 आवेदकों के विचार

31. आवेदक ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग ने अपने निष्पादन में सुधार किया है और उसे कोई वास्तविक क्षति नहीं होती है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग जिसका प्रतिनिधित्व एकमात्र उत्पादक मै0 दीपक लिमिटेड द्वारा किया गया है, ने अपनी लाभप्रदता में सुधार किया है और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों में कमी नहीं की है। अतः घरेलू उद्योग को इसी से होने वाले निर्यात के कारण क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है। अतः यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं बनता है कि ईयू से होने वाले आयातों के कारण क्षति हुई हो और अतः इसमें कोई कारणात्मक संबंध भी नहीं बनता।

च. 2.2 आयातक के विचार

32. मै0 विर्चोव लेबोरेट्रीज के विचार सारांश में नीचे दिए गए हैं

- i) विर्चोव लेबोरेट्रीज लि0, हैदराबाद (जिसे इसके बाद विर्चो लैब कहा गया है) ने

- ईयू सं.रा. अमरीका तथा जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोक्सल एमाइन सल्फेट (एचएस) के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के मामले में ईयू के निर्यातकों की ओर से यूरोपीय आयोग द्वारा समीक्षा संबंधी आवेदन-पत्र का समर्थन किया है ।
- ii) विर्चोव लेबोरेट्रीज लि० विश्व में सल्फोमेथोक्साजोल का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका उत्पादन 4800 मी.टन. प्रति वर्ष है । एचएस एक ऐसा महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग सल्फोमेथोक्साजोल के विनिर्माण में किया जाता है ।
- iii) उन्होंने निवेदन किया है कि उन्होंने घरेलू उद्योग से एचएस की खरीद नहीं की है । घरेलू उद्योग उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से काफी घटिया है । वास्तव में, यह निवेदन है कि उन्होंने जांच के अधीन उत्पाद का आयात करना जारी रखा है और उन्होंने क्वालिटी अन्तर की वजह से इसे घरेलू उद्योग से खरीदने की बजाय उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क अदा किया है ।
- iv) घरेलू उद्योग द्वारा ऑफर की गई कीमतें पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद आयातित उत्पाद की लैंडेड लागत की तुलना में कम कीमत पर रही हैं । घरेलू उद्योग द्वारा ऑफर की गई कीमत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बिक्री हेतु उपलब्ध उत्पाद की कीमत की तुलना में काफी कम है । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को किसी तरह से लाभ नहीं हुआ है । यह निवेदन है कि भारत में ऐसे कई एकक हैं जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात एसएमएक्स/एसएमजेड के अन्तिम उत्पाद का विनिर्माण करने के प्रयोजन से किया है अथवा अन्य औषधियों को एचएस उद्योग की अअर्थक्षमता के कारण बंद होना पड़ा ।
- v) घरेलू उद्योग ने उक्त माल के अंतिम प्रयोक्ताओं को 55 रु० से लेकर 60 रु० तक की कीमत पर बिक्री करने की ऑफर की है । यह कीमत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उपलब्ध उत्पाद की कीमत की तुलना में काफी कम है जो 80 से 85 रु० तक की कीमत पर उपलब्ध होती । यद्यपि, आयात लाइसेंस के तहत आयातित माल का मूल्य उसके लैंडेड मूल्य से अधिक है अथवा घरेलू उद्योग द्वारा ऑफर की गई कीमत पर ।

- vi) घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में इस माल की बिक्री संदर्भित कीमत की तुलना में कहीं कम कीमत पर कर रहा है और घरेलू उद्योग की मौजूदा उत्पादन लागत पहले ही निर्धारित संदर्भित कीमत की तुलना में कम है क्योंकि आयातित माल का लैंडेड मूल्य मौजूदा अक्षतिकारी कीमत से अधिक है, अतः कोई कीमत कटौती अथवा कीमत गिरावट नहीं आई है।
- vii) उन्होंने निवेदन किया है कि पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग को सहायता नहीं मिली है और कहा है कि घरेलू उद्योग के सभी क्षति कारकों में सुधार आया है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्कों के लगाए जाने के बाद पहले दो वर्षों में घरेलू उद्योग के सभ्जी घटकों में सुधार आया है लेकिन जांच की मौजूदा अवधि में उत्पादन बिक्रियों, बिक्री कीमत तथा लाभ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का यह कहना कि पाटनरोधी शुल्कों से घरेलू उद्योग को सभी क्षति कारकों में सुधार आया है फिर भी इस बात के लिए कोई कारण नहीं है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट क्यों आई है। इससे यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के अन्य कारण भी हो सकते हैं। देश में एचएएस की मांग लगभग 7000 मी.टन है। घरेलू उद्योग की एचएएस उत्पाद की क्षमता लगभग 1500 मी.टन है। घरेलू उद्योग के लिए स्पष्ट बाजार लगभग 2000 मी.टन. (एसएमएक्स की मांग को छोड़कर) है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी यदि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता उपयोग का लक्ष्य 100% तक प्राप्त नहीं कर सकता है तो पाटन के अलावा कोई और कारण भी हो सकते हैं।
- viii) यह संभव नहीं है कि क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना हो जाए क्योंकि एसएमएक्स के उत्पादक कभी भी घरेलू उद्योग के ग्राहक नहीं रहे और निकट भविष्य में भी यह प्रतीत नहीं होता है कि एसएमएक्स उत्पादकों की जरूरत क्वालिटी तथा क्षमता के कारण घरेलू उद्योग द्वारा पूरी की जा सके। अतः जब तक एचएएस की मांग कम नहीं हो जाती तब तक आयात मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा।

च.2.3 घरेलू उद्योग के विचार

33. घरेलू उद्योग के विचार सारांश में नीचे दिए जा रहे हैं

- i) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि भारत को मैसर्स बीएएसएफ द्वारा अग्रिम लाइसेंस योजना पर निर्यात को छोड़कर अन्तिम उपयोग के लिए कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं हुए हैं क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगा दिया गया था। उन्होंने आगे

यह भी निवेदन किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता में सुधार कर सका है और मांग के संबंध में अपने बाजार हिस्से में वृद्धि कर सका है । यद्यपि घरेलू उद्योग का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा लेकिन घरेलू उद्योग का निवेदन है कि इस कारण मौजूदा शुल्क को पहले समाप्त करने संबंधी आधार नहीं है । घरेलू उद्योग में आगे इसलिए भी सुधार नहीं हो पाया क्योंकि अन्य देश के उत्पादकों ने संबद्ध माल के पाटन का सहारा लिया है । इसके अलावा, उपभोक्ता अग्रिम लाइसेंस प्रावधानों का अवांछित लाभ उठा रहे हैं और वे अंतिम उत्पाद में प्रयुक्त आयातों का सहारा ले रहे हैं । वास्तव में, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है । इसके अलावा, हालांकि यह सत्य है कि इस उत्पाद का पाटन बेलारूस से हो रहा है लेकिन घरेलू उद्योग का निवेदन है कि यह मौजूदा शुल्क समाप्त करने के लिए आधार नहीं बन रहा है ।

- ii) उन्होंने निवेदन किया है कि घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2001-02 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद 2002-03 में उसमें गिरावट आई है और इसमें जांच अवधि के दौरान मामूली वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि जांच अवधि के दौरान बिक्री मात्रा में हुई वृद्धि इस संबद्ध माल की बिक्री कीमत में आई गिरावट के कारण है । घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है क्योंकि संबद्ध देशों से संबद्ध माल का पाटन जारी रहा । क्षमता उपयोग में वर्ष 2001-02 के 70% की तुलना में जांच अवधि के दौरान घटकर 61% रह गया ।
- iii) घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानि की स्थिति से उबरने के बाद वर्ष 2002-03 तक लाभ दर्ज कराया । किंतु, उसे जांच अवधि के दौरान पुनः वित्तीय हानि हुई क्योंकि संबद्ध माल की बिक्री कीमत में मूल रूप से गिरावट आ गई थी । उन्होंने निवेदन किया है कि संबद्ध माल की उत्पादन लागत में मामूली गिरावट आई है जबकि बिक्री कीमत में संबद्ध माल की उत्पादन लागत में कहीं ज्यादा गिरावट आई थी । इससे उद्योग को वित्तीय हानि उठाने पर बाध्य होना पड़ा ।
- iv) परिचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह की स्थिति में वर्ष 2002-03 में सुधार हुआ लेकिन इसमें जांच अवधि के दौरान गिरावट आ गई । इसी प्रकार, पूंजी निवेश पर आय जो वर्ष 2000-01 में 19% रही थी, उसमें जांच अवधि के दौरान नकारात्मक होने से पहले वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 में सुधार हुआ ।
- v) एक बार फिर, प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है क्योंकि रोजगार के स्तर में कमी होने के बावजूद उत्पादन में गिरावट आई । घरेलू उद्योग में

उत्पादकता तथा वित्तीय स्तर में सुधार करने के प्रयास से उसके वडोदरा संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या में कमी आई जिसका संबद्ध माल पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि जांच अवधि के दौरान मजदूरियों में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई।

- vi) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है जब संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आई जिससे विदित होता है कि घरेलू उद्योग में मौजूदा पाटनरोधी उपायों के कारण स्थिति में सुधार आया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू मांग में गिरावट के बावजूद संबद्ध देशों का हिस्सा कुल मांग में 50% से भी अधिक रहा। मांग में कमी के बावजूद घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा न केवल अच्छा रहा बल्कि उसमें वृद्धि हुई है। उन्होंने निवेदन किया है कि ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क में संभावित समाप्ति से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पुनः हानि आएगी।
- vii) संबद्ध देशों से आयात का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा अक्षतिकारी कीमत की तुलना में काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप भयंकर कीमत कटौती हो रही है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है क्योंकि संबद्ध माल का लैंडेड मूल्य घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में काफी कम है।
- viii) घरेलू उद्योग के पास संबद्ध माल का औसत स्टॉक इस अवधि में बढ़ता रहा है। घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक कारकों पर वर्ष 2002-2003 तक सकारात्मक रही है जो जांच-अवधि के दौरान नकारात्मक हो गई है। इस दृश्य में उन्होंने निवेदन किया है कि वे एचएएस संयंत्र में अतिरिक्त पूंजीनिवेश नहीं कर पाए ताकि पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके।
- ix) सामान्य रूप से, घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2000-01 और वर्ष 2002-2003 के बीच सुधार आया है किन्तु, जांच-अवधि में एक बार पुनः बिगड़ गया और उन्होंने निवेदन किया है कि यह अवनति पाटित आयातों की मौजूदगी की वजह से हुई है।
- x) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उन्हें संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से सतत वास्तविक क्षति हुई है और शुल्क को संभावित रोक दिए जाने से घरेलू उद्योग को और आगे क्षति होगी क्योंकि पाटित आयातों को घरेलू बाजार में पहुंच मिल जाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान बदली हुई स्थिति में घरेलू उद्योग क्षति के प्रति

असुरक्षित है यदि इन उपायों को समाप्त किए जाने अथवा उनमें कटौती किए जाने की अनुमति दी जाती है।

- xi) आयातों का बाजार हिस्सा महत्वपूर्ण रहा है। क्षति-अवधि के दौरान बाजार हिस्से में गिरावट पाटनरोधी शुल्क के अर्थदण्ड के कारण आया है और आयात अधिकांशतया शुल्क मुक्त योजना के तहत हुए हैं।
- xii) संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन निर्धारित सीमाओं की तुलना में अधिक है और यह काफी अधिक हैं। मूल जांच में भी पाटन मार्जिन काफी रहा।
- xiii) घरेलू उद्योग का निवेदन है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से होने वाले पाटित आयातों के कारण हुई और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाते हैं तो पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग को शुल्क बढ़ जाएंगे।
- xiv) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि बेलारूस से आयातों की वजह से भी घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है क्योंकि ये आयात भी पाटित कीमतों पर हो रहे हैं। अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा मूल्य न्यूनतम रहे।
- xv) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मांग में गिरावट दर्शायी गई। घरेलू उद्योग का निवेदन है कि आयात अधिकांशतया शुल्क मुक्त योजना के तहत आते हैं। यदि इन आयातों पर विचार किया जाता है तो तब मांग में प्रगतिशील वृद्धि दर्ज होगी।
- xvi) घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है। अतः घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियाँ अथवा प्रतिस्पर्धा की शर्तें क्षति का संभाव्य कारण नहीं हो सकती हैं।
- xvii) प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि इसी का यह मानना कि बदली हुई परिस्थिति-समीक्षा के तहत क्षति संबंधी जांच पाटन की जांच किए बिना इस जांच के साथ-साथ एक आधार है, यथोचित प्रतीत नहीं होता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन तथा क्षति-निर्धारण दोनों की ही जांच डब्ल्यूटीओ करार के तहत दायित्व के अनुसार ठीक ही की है।

च. 2.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 तथा अनुबंध-II में प्राधिकारी से यह अपेक्षा

है कि वह समान वस्तु के संबंध में घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और पाटित आयातों के प्रभाव और ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की जांच करे। चूंकि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए इन आयातों को पाटित आयात माना गया है अतः प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत-प्रभाव की जांच की जाए और यह निर्धारित करने के लिए क्षति-कारकों का विश्लेषण किया जाए कि क्या घरेलू उद्योग का ऐसे पाटित आयातों की वजह से वास्तविक क्षति का होना जारी है।

आयात-मात्रा तथा आयात-कीमतें

35. क्षति-विश्लेषण-अवधि के लिए डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि क्षति-जांच-अवधि के दौरान आयात संबद्ध देशों/क्षेत्रों सहित अनेक स्रोतों से हुए हैं। तदनुसार, डीजीसीआईएण्डएस द्वारा दिए गए आयात-आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं-

एमटी	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जांच अवधि
ईयू	2288	1394	1086	764
यूएसए	617	549	361	111
संबद्ध देश	2905	1943	1447	875
अन्य देश	1018	1634	1631	1035
कुल आयात	3923	3578	3078	1910
आयातों में हिस्सा				
संबद्ध देश	74.05	54.32	47.02	45.82
अन्य देश	25.95	45.68	52.98	54.18

36. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आयात-मात्रा में एमग्र रूप में गिरावट रही। यह वर्ष 2000-2001 के दौरान 3923 मी.टन के हुए जो जांच-अवधि में घटकर 1910 मी.टन के रह गए जबकि अन्य देशों से हुए आयात जो वर्ष 2000-01 में 1018 मी.टन के हुए थे, बढ़कर जांच-अवधि में 1035 मी.टन के हो गए। यह बात नोट की जाती है कि कुल आयातों में संबद्ध देशों से किए गए कुल आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2000-2001 में 74.05% रहा था, जांच-अवधि के दौरान घटकर 45.82% रह गया और अन्य देशों से हुए कुल आयातों में इन आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2000-2001 के दौरान 25.95% रहा था, जांच-अवधि में वह

बढ़कर 54.18% हो गया। जहाँ तक कीमतों का संबंध है, यह 2000-2001 के 37248 रु./मी.टन से बढ़कर जाँच अवधि में 42889 रु./मी.टन हो गया।

घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग

37. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग और इन कारकों पर पाटित आयातों के प्रभाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में उसके निष्पादन की भी जांच की गई है। घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2000-2001 के दौरान 1180 मी.टन हुआ था, घटकर जांच अवधि में 952 मी.टन रह गया। घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता क्षति-अवधि के दौरान समान-स्तर पर ही रही और क्षमता उपयोग जांच अवधि के दौरान घट गया क्योंकि इस दौरान मांग-परिदृश्य में गिरावट का रुख रहा।

वर्ष	प्रतिस्थापित क्षमता	उत्पादन(सभी उत्पाद)(मी.टन)	क्षमता उपयोग (%)
2000-01	1560	1180	76
2001-02	1560	1178	76
2002-03	1560	1035	66
2003-04	1560	952	61

मांग तथा बाजार हिस्से

38. कुल मांग का प्राक्कलन घरेलू बिक्रियों की मात्रा और अन्य देशों से हुए आयातों और साथ ही, संबद्ध देशों से घरेलू बाजार में हुए आयातों के आधार पर किया गया है।

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जांच-अवधि
मांग(मी.टन)				
घरेलू बिक्रियां	1018	1183	850	923
संबद्ध देशों से आयात	2905	1943	1447	875
अन्य देशों से आयात	1018	1634	1631	1035
कुल आयात	3923	3578	3078	1910
कुल मांग	4942	4760	3928	2833
बाजार				

हिस्सा(%)				
घरेलू उद्योग	21	25	22	33
संबद्ध देश	59	41	37	30
अन्य देश	20	34	41	37

39. संबद्ध माल की मांग में अत्यधिक गिरावट आई है क्योंकि यह वर्ष 2000-2001 के दौरान 4942 मी.टन की रही जो जांच-अवधि में घटकर 2833 मी.टन की रह गई। साथ ही, आयातों में भी समग्र संख्या और बाजार हिस्से, दोनों ही दृष्टियों से गिरावट रही है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2000-2001 में 21% रहा था, जांच अवधि में बढ़कर 33% हो गया जबकि संबद्ध देशों के पाटित आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट दर्शायी गई है और जांच अवधि में इसमें 29% की गिरावट आई है। किन्तु, गैर-पाटित स्रोतों के आयातों में कुल मांग में 17% की वृद्धि रही है। अतः ये आंकड़े यह इंगित करते हैं कि शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की दशा में उसके बाजार रस्से की दृष्टि से काफी सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा-प्रभाव नहीं पड़ा है।

घरेलू उद्योग की बिक्री वसूली

40. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत जो वर्ष 2000-2001 में 100 पर रही थी, वह जांच-अवधि में घटकर 81 रह गई। इस प्रकार, इसमें वर्ष 2000-2001 के स्तर में 19% की काफी गिरावट दर्शायी गई है। उत्पादन-लागत में भी पिछले तीन वर्षों में काफी गिरावट रही है। घरेलू उद्योग की उत्पादन-लागत और निबल बिक्री कीमतें उसके रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई हैं:-

सूचीकृत आंकड़े

वर्ष	उत्पादन तथा बिक्री लागत प्रति मी.टन(रु०)	बिक्री कीमत/मी.टन (रु०)	लाभ/हानि प्रति मी.टन (रु०)
2000-2001	****	****	****
2001-2002	****	****	****
2002-2003	****	****	****
2003-2004	****	****	****

41. यह देखा गया है कि उत्पादन लागत में काफी गिरावट रही है क्योंकि यह 2000-2001 में 100 से घटकर जांच अवधि में 76 रह गई और बिक्री कीमतों में तदनुरूपी गिरावट 19% की रही है। किन्तु, घरेलू उद्योग की उत्पादन-लागत

में गिरावट उसकी बिक्री कीमतों की तुलना में काफी अधिक है। घरेलू उद्योग की हानि जो वर्ष 2000-2001 में 100 पर रही थी, उसकी वित्तीय स्थिति में क्षति-अवधि के दौरान काफी सुधार आया और जांच-अवधि में उसे 764 तक का लाभ हुआ है। शुल्क लगाए जाने के बाद इस उत्पाद के प्रति मी.टन लाभ में काफी सुधार दर्शाया गया है। किन्तु उसमें वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के बीच गिरावट दर्शायी गई है।

कीमत कटौती

42. जांच-अवधि के लिए संबद्ध माल के संबंध में पाटित आयातों के भारित औसत लैण्डेड मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई। संबद्ध देशों से आयात का लैण्डेड मूल्य जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल हेतु घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली की तुलना में कम रहा। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती रही। मार्जिन कटौती जांच अवधि के दौरान 7% से 16% के बीच रही।

कीमत कटौती	ईसी	यूएसए	संबद्ध देश
निबल बिक्री वसूली	****	****	****
लैण्डेड मूल्य	52724	63114	54040
कीमत कटौती	****	****	****
कीमत कटौती %	****	****	****

कम दाम पर बिक्री कीमत

43. कम दाम पर बिक्री कीमत क्षति के आंकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने अक्षतिकारी कीमत की गणना की है और उसकी तुलना लैण्डेड मूल्य से की ताकि कम दाम पर बिक्री की कीमत की सीमा निर्धारित की जा सके। घरेलू उत्पादक के लिए अक्षतिकारी कीमत का मूल्यांकन जांच-अवधि के दौरान विवचाराधीन उत्पाद के संबंध में उत्पादन-लागत पर समुचित रूप से विचार करके किया गया है। इसके अलावा, अकुशलताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से क्षमता उपयोग को नियामक बनाया गया है। यह विश्लेषण यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध माल का भारित औसत लैण्डेड मूल्य जांच-अवधि के लिए घरेलू उद्योग के संबंध में निर्धारित अक्षतिकारी कीमत से भी कम है। जांच-अवधि के दौरान कम दाम पर बिक्री का मार्जिन 5% से 15% तक रहा।

कीमत कटौती	ईसी	यूएसए	संबद्ध देश
अक्षतिकारी कीम	****	****	****
लैंडेड मूल्य	52724	63114	54040
कम बिक्री कीम	****	****	****
कम बिक्री कीमत(%)	****	****	****

44. इसके अलावा, संबद्ध माल का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में कम रहा। इस प्रकार, घरेलू बिक्री कीमतों में कटौती हुई। किन्तु यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री कीमत घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित अक्षतिकारी कीमत की तुलना में अधिक रही है।

अन्य क्षतिकारक

45. घरेलू उद्योग की मात्रा तथा कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और आयातों की मात्रा तथा मूल्य जैसे प्रमुख क्षति-संकेतकों, घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्रियों और पिछले भाग में विभिन्न खण्डों के बाजार हिस्से से मांग पैटर्न की जांच करने के बाद घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी के संकेतक आर्थिक कारकों का भी निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है-

लाभप्रदता

46. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का विश्लेषण कम्पनी के रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है -

वर्ष	उत्पादन तथा बिक्री-लागत प्रति मी.टन (रु०)	बिक्री कीमत/मी.टन (रु०)	सूचीकृत आंकड़े	
			लाभ/हानि	प्रति मी.टन (रु०)
2000-2000	****	****	****	
2001-2002	****	****	****	
2002-2003	****	****	****	
2003-2004	****	****	****	

47. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जो 2000-2001 के दौरान 100 पर रही थी वह जांच अवधि के दौरान बढ़कर 764 हो गई । इसमें जांच-अवधि के दौरान निश्चित रूप से गिरावट आई है । यदि इसकी पिछले वर्षों से तुलना की जाए । किन्तु आधार वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग के हानि-परिदृश्य में लाभ हुआ है । उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि जांच-अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में सुधार आया है ।

रोजगार

48. घरेलू उद्योग ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है क्योंकि इसका उत्पादन जो 2000-2001 के दौरान 100 पर रहा था वह जांच-अवधि के दौरान घटकर 81 रह गया । किन्तु प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2% से भी अधिक की गिरावट आ गई । अतः यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं बन सकता है । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कर्मचारियों की संख्या में कटौती उत्पादकता में सुधार हेतु लागत कटौती उपाय के रूप में की गई है । यह नोट किया जाता है कि रोजगार के स्तर में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	उत्पादन(किग्रा.)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (किग्रा.)
2000-2001	100	100	100
2001-2002	121	100	82.30
2002-2003	90	88	97.50
2003-2004(जांच अवधि)	83	81	97.68

मजदूरियाँ

49. संबद्ध माल की मजदूरियों में वृद्धि हुई है क्योंकि यह वर्ष 2000-2001 के दौरान जो 100 पर रही थी, वह जांच अवधि के दौरान बढ़कर 122 हो गई और साथ ही, बिक्रियों की प्रतिशत मजदूरी में भी वृद्धि दर्शायी गई है । यह 2000-2001 के दौरान 100 पर रही थी, जांच अवधि में वह बढ़कर 130.25 हो गई । घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी मजदूरी एवं वेतन जांच-अवधि के दौरान बढ़ गया है । किन्तु, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग अपनी मजदूरियों में वृद्धि किए जाने

के बाद भी यथोचित लाभ कमा रहा है। अतः मजदूरियां घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारक नहीं बन सकती है।

वर्ष	प्रति मी.टन मजदूरियां	बिक्रियों की % मजदूरी	प्रति कर्मचारी मजदूरियां
2000-2001	100	100	100
2001-2002	96	84.94	79
2002-2003	115	125.27	112
2003-2004 (जांच अवधि)	122	130.25	119

उत्पादकता

50. इस अवधि के दौरान उत्पादन में गिरावट के कारण प्रति कर्मचारी उत्पादन की दृष्टि से उत्पादकता में मामूली गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में, जैसाकि प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में परिलक्षित है, जांच-अवधि के दौरान 2% की गिरावट आई है जबकि इसी अवधि में उत्पादन 100 से घटकर 81 रह गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्पादकता में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	उत्पादन(किग्रा.)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (किग्रा.)
2000-2001	100	100	100
2001-2002	121	100	82.30
2002-2003	90	88	97.50
2003-2004 (जांच अवधि)	83	81	97.68

माल सूची

51. कम्पनी की माल सूची-स्थिति में काफी सुधार दर्शाया गया है। घरेलू उद्योग के स्टॉक जो वर्ष 2000-2001 के दौरान 100 पर रहे थे वह जांच अवधि में 16.31

रह गए और बिक्री प्रतिशत के रूप में यह जो वर्ष 2000-2001 के दौरान 100 पर रहा था वह जांच-अवधि के दौरान घटकर 16.31 रह गया ।

सूचीकृत

वर्ष	मासिक बिक्रियों का %	अन्तिम मी.टन स्टॉक
2000-2001	100	100
2001-2002	4.44	5.15
2002-2003	136.17	113
2003-2004	18.01	16.31

पूंजी निवेश और पूंजी निवेश पर आय

52. जांच-अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा कोई क्षमता वृद्धि अथवा कोई उल्लेखनीय नया पूंजी निवेश नहीं किया गया है । घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता में समनुरूप से सुधार करता है । घरेलू उद्योग को आधार वर्ष की नकारात्मक आय से जांच अवधि के दौरान सकारात्मक आरओसीई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है ।

वर्ष	सूचीकृत
2000-2001	-100
2001-2002	91
2002-2003	154
जांच अवधि	49

नकद प्रवाह

53. घरेलू उद्योग क्योंकि बहु-उत्पादन संयंत्रों वाली एक बहु-उत्पाद कंपनी है अतः इस उत्पाद के नकद-प्रवाह की वास्तविक राशि का निर्धारण करना संभव नहीं है। किन्तु, यह पाया गया है कि कंपनी ने क्षति-अवधि के दौरान इस उत्पाद के नकद लाभ में काफी सुधार किया है ।

पाटन की मात्रा

54. पाटन-मात्रा उतनी सीमा तक एक संकेतक के रूप में जितनी से घरेलू उद्योग को पाटित आयात क्षति कर सकते हैं, यह दर्शाता है कि जांच-अवधि के लिए

संबद्ध देशों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन काफी हैं, हालांकि पाटनरोधी शुल्क लागू हैं ।

कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक

55. लागत-ढांचे में परिवर्तन, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापनों की कीमतों की उन कारकों के विश्लेषण के लिए जांच की गई है जिनमें घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पाटित आयात शामिल नहीं हैं । इस उत्पाद का कोई अन्य अर्थक्षम प्रतिस्थापन नहीं होता है और मै0 दीपक निद्राइट ही भारत में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है । अतः घरेलू प्रतिस्पर्धा से कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

गंवाई गई संविदाओं का साक्ष्य

56. घरेलू उद्योग में संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयातों के कारण आर्डर अथवा संविदा गंवाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अतः संविदा गंवाना घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कोई कारण नहीं माना जा सकता है ।

निष्कर्ष

57. क्षति-कारकों की जांच के आधार पर यह नोट किया जाता है कि कुल मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । संबद्ध देशों से कुल आयातों में जांच-अवधि के दौरान आधार-वर्ष की तुलना में लगभग 50% की गिरावट रही है जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा घरेलू बिक्रियों में संबद्ध माल की कुल मांग में गिरावट के समानुपात में गिरावट नहीं रही है । घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच-अवधि के दौरान सुधार हुआ है । घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी क्षति-अवधि के दौरान सुधार हुआ है । घरेलू उद्योग की माल सूची स्थिति में भी जांच-अवधि के दौरान वृद्धि दर्शायी गई है और मासिक बिक्री के प्रतिशत में भी सुधार हुआ है । संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती हो रही है लेकिन घरेलू उद्योग उसके लिए निर्धारित अक्षतिकारी कीमत से भी अधिक बिक्री कीमत प्राप्त कर रहा है ।

च.3 अन्य ज्ञात कारक

अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

मी.टन	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जांच-अवधि
संबद्ध देश	2905	1943	1447	875
अन्य देश	1018	1634	1631	1035
कुल आयात	3923	3578	3078	1910
संबद्ध देश	74.05	54.32	47.02	45.82
अन्य देश	25.95	45.68	52.98	54.18

58. जांच-अवधि के दौरान बेलारूस सहित संबद्ध देशों को छोड़कर अनेक अन्य देशों से आयात किए गए हैं। अन्य स्रोतों से किए गए कुल आयातों में वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2000-2001 में 1018 मी.टन के रहे जो बढ़कर जांच अवधि में 1035 मी.टन के हो गए, किन्तु, यह नोट किया जाता है कि जांच-अवधि के दौरान अकेले बेलारूस से 356 मी.टन का निर्यात किया गया। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इन स्रोतों से भारित औसत आयात कीमत और संबद्ध देशों से आयात-कीमत कमोबेश एक समान है। अतः अन्य स्रोतों से हुए आयातों का भी घरेलू उद्योग पर मात्रा तथा मूल्य दोनों दृष्टियों से प्रभाव पड़ रहा है प्रतीत होता है।

मांग में कमी और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-04
मांग	4942	4760	3928	2833
सूचीकृत	100	96.33	79.48	57.33

59. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग जो 4942 मी.टन की रही थी, वर्ष 2001-2002 में बढ़ गई और जांच-अवधि में घटकर 2833 मी.टन रह गई और बाद में दोनों वर्षों में घट गई। मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट के मांग परिदृश्य में काफी वृद्धि दर्शायी गई है जबकि संबद्ध देशों के हिस्से में गिरावट रही है। साथ ही, अन्य स्रोतों से हुए आयातों का हिस्सा कुल मांग में 21% से बढ़कर 37% हो गया।

व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

60. संबद्ध माल मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई भी व्यापार

प्रतिबंधात्मक पद्धतियां मौजूद नहीं हैं। घरेलू उद्योग ही देश में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है। इसके अतिरिक्त, अन्य स्रोतों से आयात की भारतीय बाजार में काफी अधिक मौजूदगी हो रही है जिसमें संबद्ध देशों से आयात के साथ-साथ काफी वृद्धि हुई है।

प्रौद्योगिकी का विकास तथा निर्यात निष्पादन

61. किसी भी इच्छुक पक्षकार ने घरेलू उद्योग को क्षति के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी अथवा प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे नहीं उठाए हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान बाजार-प्रवेश अभियान के रूप में एक छोटी सी मात्रा का निर्यात किया है और इससे कंपनी की लाभप्रदता पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

62. श्रमिक उत्पादन और प्रतिदिन उत्पादन की दृष्टि से घरेलू उद्योग की उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्शाई गई है। किंतु, यह नोट किया जाता है कि उत्पादन में यह मामूली गिरावट नगण्य है।

च.4 पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

63. चूंकि प्राधिकारी ने यह पहले ही निर्धारित कर दिया है कि संबद्ध माल का संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी है, अतः पाटन की पुनरावृत्ति का विश्लेषण करना अपेक्षित है। किंतु, संबद्ध देशों में इस उत्पाद के सामान्य मूल्य पर विश्वास योग्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए यह यथोचित निष्कर्ष हो सकता है कि निर्यात का पाटित कीमतों पर बाजार में प्रवेश होना जारी रहेगा। लेकिन भारतीय बाजार में सभी स्रोतों से इस उत्पाद के प्रवेश की कीमत को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि निर्यात कीमतों में तत्काल और आगे गिरावट नहीं होगी।
64. अतः, इस बात की जांच करना प्रासंगिक है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति की इन पाटन आयातों के कारण पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यदि यह शुल्क हटाया जाए अथवा उसमें कमीबेशी की जाती है। यह पहले साबित कर दिया गया है कि संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का लैंडेड मूल्य

घरेलू उद्योग की बिक्री और प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से कम रहती है। किंतु, प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध माल की निवल बिक्री वसूली घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित अक्षतिकारी कीमत की तुलना में कम है। अतः, संदर्भित कीमत की दृष्टि से निर्धारित शुल्क को हटाए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग पर वास्तविक कुप्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

65. किंतु, वास्तविक क्षति की जांच के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति अथवा क्षति की आशंका की संभावना की प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर जांच की गई है।
66. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि वास्तविक क्षति की जांच उक्त नियमावली के अनुबंध II(vii) की दृष्टि से की जाए, जो इस प्रकार है:-

" वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि मात्र दोषारोपण, अटकलबाजी अथवा अप्रत्यक्ष संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिससे कि ऐसी स्थिति बन जाए जिससे पाटन के कारण क्षति हो, को स्पष्ट रूप से पहले ही देखा जाना चाहिए और वह आसन्न हो। वास्तविक क्षति की आशंका होने संबंधी निर्धारण करने में प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर भी विचार करेगा और ;

- (क) भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की पर्याप्त दर जिसमें पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना हो;
- (ख) पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य अथवा आसन्न, निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि जिसमें भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना इंगित हो जो अतिरिक्त निर्यातकों को आत्मसात करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया हो;
- (ग) क्या आयातों का ऐसी कीमतों पर प्रवेश हो रहा है जिसका घरेलू कीमतों पर काफी दबाव अथवा दबावकारी प्रभाव हो और जिससे और अधिक आयात की मांग में वृद्धि होने की संभावना हो; और
- (घ) ऐसी वस्तु की माल सूची की जांच की जा रही हो।"

67. हालांकि किसी स्पष्ट उपबंध के अभाव में उपर्युक्त प्रावधान किसी समीक्षा जांच में क्षति की संभाव्य पुनरावृत्ति की जांच हेतु यथोचित कारक प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्राधिकारी ने इस विषय पर अनुमान निकालने के लिए इन कारकों की जांच की है।
68. मौजूदा मामले में संबद्ध माल के आयातों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और मांग में कुछ और आयात करने के वास्ते गिरावट भी आई है। यह नोट किया जाता है कि आसन्न क्षति की आशंका के अपने समर्थन में घरेलू उद्योग ने साक्ष्य पुष्ट नहीं किया है और क्षति की आशंका के संबंध में पुष्ट साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी को यह यथोचित नहीं लगा कि पाटनरोधी उपायों को जारी रखे जाने की सिफारिश की जाए क्योंकि मौजूदा आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। रिकॉर्ड में यह कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि इन शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होगी। किंतु, यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री कीमत, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित अक्षतिकारी कीमत की तुलना में अधिक है।

छ. कारणात्मक संबंध

69. कारणात्मक संबंध के मुद्दे के बारे में इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत निवेदनों की जांच की गई है। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबंधी मुद्दे और घरेलू उद्योग को होने वाली वास्तविक क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में एक विस्तृत जांच की गई। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II और पैराग्राफ (v) निम्नानुसार है:-

* यह अवश्य ही प्रदर्शित किए जाए कि उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) तथा (iv) में निर्धारित पाटन प्रभावों के ज़रिए पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संगत साक्ष्य की जांच के आधार पर होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की भी जांच करेगा कि क्या किसी ऐसे कारकों जिनमें पाटित आयात शामिल नहीं हों और जो साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों और इन अन्य कारकों की वजह से क्षति हो रही हो, को पाटित आयातों पर नहीं मढ़ना होगा। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं पाटन कीमतों पर नहीं बेचे गए आयात की मात्रा तथा कीमतें, मांग में कमी अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां तथा विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा,

प्रौद्योगिकी में विकास तथा घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता में विकास ।"

70. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मांग में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2000-01 में 21% रही थी वह जांच अवधि के दौरान बढ़कर 33% हो गई । यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की संबद्ध माल की निवल बिक्री वसूली जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित अक्षतिकारी कीमत से अधिक रही है । यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में गिरावट रही जो वर्ष 2000-01 के दौरान कुल आयातों के 74.05% रही, वह जांच अवधि के दौरान घटकर 45.82 % रह गई जबकि अन्य स्रोतों से होने वाले आयातों में वृद्धि हुई । यह वर्ष 2000-01 में 25.95% रही जो बढ़कर जांच अवधि के दौरान 54.18% हो गई । यह भी पाया जाता है कि अन्य स्रोतों से आयात जिसका 54.18% हिस्सा है, की मात्रा तथा कीमत से घरेलू उद्योग की घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

71. प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से होने वाले पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं हो रही है और मौजूदा पाटनरोधी उपायों को जारी रखना यथोचित नहीं होगा । पाटन तथा क्षति की जांच यह इंगित करती है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण इस समय कोई क्षति नहीं हो रही है और पाटित आयातों के कारण क्षति होने की संभावना भी नहीं है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि संबद्ध देशों से होने वाला पाटन अभी भी जारी है और यह घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है । घरेलू उद्योग ने आगे यह भी निवेदन किया कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी । यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से होने वाले पाटित आयातों के कारण आसन्न क्षति की उनकी आशंका के समर्थन में कोई साक्ष्य पुष्ट नहीं किया । क्षति की आशंका संबंधी पुष्ट साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी को यह यथोचित नहीं लगा कि पाटनरोधी उपायों को जारी रखे जाने की सिफारिश की जाए क्योंकि घरेलू उद्योग को मौजूदा आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है । रिकॉर्ड में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यदि इन शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होगी । अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं होगी ।

ज. अन्तिम निष्कर्ष

72. उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष देता है कि:-

- (क) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल को उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है;
- (ख) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है;
- (ग) संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयात पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।
- (घ) उपरोक्त को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी यह यथोचित समझता है कि दिनांक 1.3.2001 की अधिसूचना सं० 59/1/2001-डीजीएडी द्वारा पहले सिफारिश किए गए और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत हाइड्रोक्सील एमाइन सल्फेट (एचएस) जो ईयू, सं.रा. अमरीका तथा जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हो, के सभी आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की सिफारिश की जाए।
- (ङ.) इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के समक्ष सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती है।

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2005

Final Findings—(Mid-term Review)

Subject: Anti-Dumping (Mid-Term Review) investigations concerning imports of Hydroxyl Amine Sulphate (HAS) originating in or exported from EU, USA and Japan.

No. 15/23/2004- DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof:

A PROCEDURE

i. The procedure described below has been followed:

i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified final findings vide Notification No. 59/1/2001- DGAD dated 01/3/2001 recommending imposition of anti-dumping duties on all imports of Hydroxyl Amine Sulphate (HAS) originating in or exported from EU, USA and Japan.

ii) The original investigation in this proceeding was initiated on 03.3.2000. The Preliminary findings was issued by the Designated Authority vide Notification No. 59/1/2001-DGAD dated 04.8.2000. Final findings of the Authority were issued by the Designated Authority vide Notification No. 59/1/2001-DGAD dated 01/3/2001 and the final duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 31/2001-Cus. dated 28.3.2001.

iii) The Customs Tariff Act, 1975(as amended) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 made thereunder require the Authority to review from time to time, the need for the continued imposition of definitive anti dumping duty imposed by the Central Government.

iv) The Designated Authority, received an application from the European Union for review of the antidumping duties levied on the subject goods, on the grounds of changed circumstances. On the basis of positive information submitted by the above-mentioned applicants the Designated Authority considered that mid-term review of the anti dumping duty in force would be appropriate in view of the changed circumstances brought to the notice to the Authority. Accordingly, a public notice dated 14th September 2004, was issued and published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping mid term review investigation under Rule 23 of the Antidumping Rules read with Article 11.2 of the Agreement on Antidumping, in respect of the duty in force against the subject countries as above, to determine whether the continued imposition of the duty is required to offset dumping, and whether injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

v) Having decided to review these final findings, the Authority initiated the present investigations vide Notification No. 15/23/2004-DGAD dated 14th September 2004 to review the need for continued imposition of anti dumping duty on Hydroxyl Amine Sulphate from EU, USA and Japan (hereinafter referred to as subject countries) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975(as amended) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995(hereinafter referred to as AD Rules). This review covers all aspects of Notification No. 59/1/2001- DGAD dated 01/3/2001.

vi) After initiation of the review the Authority sent questionnaires, alongwith the initiation notification, to the following known exporters/producers in the subject countries in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information:

1. Allied Signal Inc.
101, Columbia Road,
P.O. No. 1039, Solvay 3,
Morristown
New Jersey 07962 1039, USA

2. BASF – Germany,
Josef Ritz Hugo Facus,
BASF Aktienguellsehaft,
Ludwigshafen, Germany
3. DSM
P.O. Box 6500
6401 JH HERRLEN, THE NETHERLANDS
4. UBE IND. Ltd.,
UBE Building
2-3-11 Higashi
Shingawa, Tokyo – 140-8633
Japan
5. Toagosei Company Ltd.,
14-1, Nishi-Shimbashi, I-Chome,
Minato-Ku,
Tokyo – 105, Japan
6. UBE Industries
3/11, Higashi-Shinagawa
2 Chome Shinagawa Ku
Tokyo – 140, Japan
7. M/s. BASF Aktiengesellschaft
CARL – BOSCH – STRABE, 38
67056, LUDWIGSCHAFEN,
GERMANY
8. M/s. Rhone Poulence Sa (Aventis)
Quai Paul Doumer, F-92408,
Courbevoie Cedex,
France
9. M/s. BASF South East Asia Pte., Ltd.,
7, Temasek Boulevard,
35-01, Suntec Tower One,
Singapore – 038987
10. Aventis Animal Nutrition Asia Pacific Pte. Ltd.,
1, Loyang Way 4, Singapore – 507028
11. M/s. BASF (Thai) Ltd.,
23rd Floor, Emporium Tower,
622, Sukhumvit Road,
Klongton, Klongtoey,
Bangkok – 10110, Thailand
12. M/s. BASF Corporation,
Chemicals Division,
Washingtonsite,
Pleasantviesw & Perishing, Washington, NJ 07882

vii) Notices were also sent to the domestic industry in India seeking relevant information in accordance with the Rules;

viii) The Embassies/High Commissions/ Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.

ix) Questionnaires were sent to the following known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4),

1. M/s. Glaxco India Ltd., Mumbai,
2. M/s. Siris Ltd., Hyderabad,
3. M/s. Shasun Chemicals & Drugs Ltd., Chennai,
4. M/s. Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad,
5. M/s. Cheminor Drugs Ltd., Hyderabad,
6. M/s. Godavari Drugs Ltd., Secunderabad,
7. M/s. Virchow Laboratories Ltd.,
8. M/s. SOL Pharmaceuticals Ltd., Hyderabad,
9. M/s. Herren Drugs & Pharmaceuticals, Hyderabad,
10. M/s. Hasmukh Ray & Co., Mumbai,
11. M/s. Arihant Impex, Mumbai,
12. M/s. BASF India Ltd., Mumbai,
13. M/s. Priya International, Mumbai,
14. M/s. URMI Chemicals, Mumbai,
15. M/s. Manali Chemicals, Mumbai,
16. M/s. Indian Drugs Mfrs. Assn., Mumbai,
17. M/s. Fragrance & Flavours Association of India (FFAI), Mumbai
18. M/s. Rubber Board of India, Kerala,
19. M/s. Indian Medical Association (IMA), Mumbai,
20. M/s. Indian Pharmaceutical Association (IPA), Mumbai,
21. M/s. Deepak Nitrite Ltd., Nandesari
22. Delegation of European Commission to India, New Delhi
23. M/s. BASF India Ltd., New Delhi
24. M/s. Chemox Laboratories Ltd., Mumbai
25. M/s. Allied Signal India Pvt. Ltd., New Delhi,
26. M/s. Indian Chemical Mfrs. Assn. New Delhi,
27. M/s. Organisation of Pharmaceuticals Producers of India, Mumbai,
28. M/s. Bulk Drugs Mfrs. Association (BDMA), Hyderabad,
29. M/s. Pesticides Association of India (PAI), New Delhi

x) Investigations were carried out for the period of investigation (POI) from 1st April 2003 to 31st March 2004 (12 months). However injury analysis have been carried out for the years April 2000 – March 2001, April 2001 – March 2002, April 2002 – March 2003 and the period of investigation.

xi) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;

- xii) Copies of the initiation notification were also sent to FICCI, CII and ASSOCHAM for wider circulation.
- xiii) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request.
- xiv) M/s. Deepak Nitrite Ltd, the domestic producer of the subject goods and the original petitioner in the original investigation submitted its responses opposing the review;
- xv) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- xvi) The Authority held a public hearing on 22nd December 2004 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, the applicant exporters of the subject goods from the European Union and other interested parties. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;
- xvii) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request.
- xviii) The views expressed by various interested parties in response to the initiation notification and subsequent to the public hearing are discussed in the relevant paragraphs to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in relevant paragraphs.
- xix) In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed on 2nd January, 2005 to known interested parties and comments received have been duly considered in these findings.
- xx) **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

2. The product involved in the original investigation and the current review is Hydroxyl Amine Sulphate (HAS) falling under heading No. 2825.1003 in Chapter 28 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC IIS Classification. This

classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. This being a changed circumstances midterm review investigation, the investigation covers the product covered in the original investigation. No argument has been extended, by any interested party, on the issue of product under consideration or like article and therefore, the Authority holds that the product being manufactured by the domestic industry and the product being manufactured and exported from the subject countries are like articles as per AD Rules.

C. DOMESTIC INDUSTRY:

3. In the original investigation the application for anti-dumping investigation was filed by M/s. Deepak Nitrite Ltd., on behalf of the domestic industry. They were the major producer of the subject goods in India and had the required standing to file the petition under AD Rules. In this mid-term review M/s. Deepak Nitrite Ltd., is the sole producer of the subject goods in India and therefore accounts for total production of the subject goods and constitute domestic industry within the meaning of AD Rules.

D. INITIATION OF THE REVIEW AND ARGUMENTS RAISED

D.1 VIEWS OF APPLICANTS

4. Views of the applicant are summarized below

i) The applicant has submitted since the imposition of anti-dumping duties there has been no direct sales of the subject goods except the exports by M/s. BASF under Advance Licence for re-exports of Sulphamethoxazole. However if the direct sales of the subject goods were to resume, dumping margin would be de-minimis as ex-works domestic sales price works out as Euro ****/Kg. and ex-factory export price works out to be Euro ****/Kg. On the basis of above export price and normal value the dumping margin of the subject goods exported from EU is negligible.

ii) The applicant has argued that the AD measures in the original investigation have not led to any improvement in the market share of the domestic industry in total demand. It is further submitted that the subject goods attracting anti-dumping duty has been replaced by dumped imports from other sources mainly Belarus. The domestic industry could not improve its market position despite the anti-dumping duty in place which demonstrates that the injury has never been caused by exports from EU.

iii) The applicant has submitted that the domestic demand of HAS has decreased due to imposition of AD measures. They have further argued that due to intense competition from Chinese exporters the prices of end product i.e., Sulphamethoxazole has decreased and as a result of which the Indian domestic users of HAS is finding difficult to compete in the International market with the Chinese anti-biotic products. The decline in demand has had a negative impact on the performance of the domestic industry.

iv) The domestic industry has proceeded in 2002 with consolidation of two of its existing divisions of Sodium Nitrite and Sodium Nitro Aeromatics. The consolidation of these two divisions have had affected the production and cost of subject goods.

v) In view of the above, applicant has submitted that exports of subject goods from EU are not the cause of injury to the domestic industry, as the injury persisted inspite of AD measures. In fact the exports from EU has been replaced by the sources non attracting anti-dumping duty and due to decrease in demand, the domestic industry could not improve its financial health even with the AD measures.

vi) However, after initiation of the review investigation the applicant failed to file questionnaire response required for determination of degree and extent of dumping if any. Subsequently, the European Commission, through whom the application for review was filed, withdrew the first ground on which review was requested i.e. no dumping from the European Union. They have argued that the request for review could stand on the injury claim alone and the dumping aspect could very well be withdrawn without prejudicing in any way the legal compliance of the EU's review request. They have further argued that in the absence of the dumping investigation in the review request, a finding on injury would still have to be made and a negative finding have to result in the termination of the measures since this is mandatory under WTO rules. They have submitted that dumping and injury determinations are not interdependent and even in the presence of dumping the duty needs to be revoked if it is found that the domestic industry suffers no material injury. Therefore, they have argued that the obligation of the applicant to provide the information on dumping is immaterial to the injury investigation which has to primarily focus on the material injury which, in their view does not exist due to change in the market dynamics, irrespective of the price charged by the EC exporters.

D.2 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

5. Views of the Domestic industry are summarized below

i). The domestic industry, in its various submissions, has opposed the initiation of the review and has *inter alia* submitted as per Indian law any review shall apply both to dumping and injury; thus, the Indian Law does not have any provision for a partial review of either dumping or injury.

ii). The domestic industry has further argued that certain Information are required to be furnished by the applicant for the review prior to initiation, which the applicants did not provide therefore, the Hon'ble Designated Authority ought not to have initiated the mid-term review on the basis of the information provided.

iii) The domestic industry has submitted that the application for the review has been filed by the European Commission on behalf of the European exporters whereas it has been stated in the initiation notification that one of a exporters from EU i.e., M/s. BASF Ltd., Germany has filed a request through the European Commission for a change circumstances mid-term review of the anti-dumping duty.

iv) The domestic industry has further argued that the applicant for the review have failed to provide the information, even after initiation of the review, in the form and manner prescribed. They argue that since the information on normal value and export prices are available with the applicant it is their primary responsibility to provide the same in the form and manner prescribed and the onus of proof in support of their claim lies with the applicant.

v) In the view of the domestic industry the information concerning cost of production and normal value are solely within the purview of the exporter. By withholding this fact, the exporter is interfering with the process of review and not acting to the best of its ability. Therefore, the exporter first be required to carry the onus placed on them by law and natural justice. The review should not have been initiated in the absence of complete evidence substantiating the claims of no dumping by the applicant exporter and no injury to the domestic industry and the burden of proof to substantiate the claim of no dumping solely lies with the applicant at the first instance before it shifts to the defending domestic industry to provide evidence of injury. They have further argued that as per the law, dumping and injury examinations are inseparable in a review and both have to be examined simultaneously to determine whether there is a likelihood of dumping and injury recurring in the event of removal or variation of the duty.

D.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

6. The Authority has taken note of the arguments of the European Commission that the dumping and injury determinations, in a changed circumstances review are two separate and distinct examinations and can be determined in isolation. The domestic industry has argued that having made a request on the grounds of no dumping and injury it was incumbent upon the European Exporters and the EC to substantiate their claims on both the counts. The EC has also claimed that continuation of dumping or no dumping during the period of investigation has no bearing on the injury examination which is a stand alone investigation to be examined on the basis of the current status of the industry.

7. Section 9A (5) read with Rule 23 of the Anti Dumping Rules provides that the Designated Authority shall from time to time review the need for continued imposition of anti dumping duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, shall recommend to the Central Govt. for its withdrawal.

8. Article 11.2 of the Agreement provides that the Authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph,

the authorities determine that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

9. The domestic industry has argued that the review should not have been initiated in the absence of complete evidence substantiating the claims of no dumping by the applicant exporter and no injury to the domestic industry and the burden of proof to substantiate the claim of no dumping solely lies with the applicant at the first instance before it shifts to the defending domestic industry to provide evidence of injury. They have further argued that as per the law, dumping and injury examinations are inseparable in a review and both have to be examined simultaneously to determine whether there is a likelihood of dumping and injury recurring in the event of removal or variation of the duty.

10. The applicants for the review have argued that dumping and injury determinations are not interdependent and even in the presence of dumping the duty needs to be revoked if the Authority determines that the domestic industry suffers no material injury. Therefore, the obligation of the applicant to provide the information on dumping is immaterial to the injury investigation which has to primarily focus on the material injury.

11. The Authority has examined these arguments and is of the view that the condition 'satisfaction' in Rule 23 refers to the satisfaction of the Authority of the need of continued imposition of duty after conducting a proper investigation and not for initiation of the review. What is required for initiating a review is positive information with the Authority on which the Authority can rely upon to decide whether a review is required to examine the need for continued imposition of the duty. In the instant case the applicant had filed positive information before the Authority in its review application and the review was initiated based on these positive information filed. Production of evidence to substantiate the claims and counter claims by various parties are the matter of investigation and are to be submitted by the parties including the party making a request for review during the course of investigation. The outcome of the review will however, depend upon the quality of evidence submitted by various parties to the review. Therefore, the Authority is of the view that the review has been correctly initiated on the basis of positive information available with the Authority which suggested that a review of the duty in force was warranted.

12. However, on the issue of separation of the dumping and injury investigation and the onus of proof to substantiate the claim of no dumping is concerned, the arguments of the applicant have been examined with reference to the Article 11.2, Article 11.3 and Article 3.4 of the Agreement. Article 11.3 provides that as a result of a review the definitive duty can be extended for a period of another 5 years term if such review covers both dumping and injury. This by implication provides for partial review covering either dumping or injury, or a comprehensive review covering both. However, the question arises whether a review covering only injury can completely overlook the degree and extent of dumping.

13. Referencing to Article 3 of the Agreement it appears that the parameters of injury to the domestic industry are to be examined with reference to the dumped imports. Article 3.1 provides that:

"A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the

dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products”.

Further Article 3.4 provides that *“the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping;”*

14. Therefore, it appears from the above express provisions of the Agreement that any examination of the condition of the domestic industry in the context of an antidumping investigation has to take into account the underlying effects of the dumping and the magnitude of dumping both in terms of volume and margins.

15. Article 11.2 of the AD Agreement enumerates that even if the express provisions of Article 11.2 are broken into two separate parts as has been interpreted by the EC, the second sentence of the proviso provides that the party can ask for a review and Authorities would examine “whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied”. This proviso requires the Authority to examine current injury if any and whether injury can recur if duties are removed. While considering the second part of the proviso the extent of dumping would be a very vital element to determine whether the domestic industry will be injured if the duties are removed even if it does not suffer any injury due the duty protection available.

16. All the above provisions of the Agreement imply that even if a partial review is required to be carried out to examine the condition of the domestic industry in order to decide whether the duty is required to be continued, by implication dumping examination becomes an integral part of the examination and in addition to the current status of dumping and current health of the domestic industry whereas the review has to examine whether a likelihood of recurrence of injury exists. Therefore, the contention of the EC that injury investigation under a changed circumstances review is a stand alone investigation and can be conducted irrespective of whether dumping continues or not, does not appear to be appropriate.

17. The EC has also submitted that the dumping examination could very well be withdrawn from their review request and this would not prejudice in any way the legal compliance of the EC's review request. In this connection it may be noted that once a review is initiated based on the positive information submitted by the interested parties, it is the responsibility of the contesting parties to put forward their respective claims and counter claims on various aspects, including dumping and injury. If the EC wishes to withdraw its claim of no-dumping and the domestic industry produces evidence of dumping by the EU producers, the Authority would have no option but to examine under the best facts clause in terms of article 6.8 of Anti Dumping Agreement.

18. With response to the disclosure statement the domestic industry has submitted that during the course of investigation, the European Commission has filed additional submission in addition to initial petition filed by them. In this respect the Authority

would like to mention that the public file has been examined by the domestic industry which contains all the non-confidential submissions filed by the interested parties during the investigation.

METHODOLOGY FOR CALCULATION OF DUMPING MARGIN:

E. DUMPING DETERMINATION: NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1 THE EUROPEAN UNION

NORMAL VALUE

19. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975. None of the exporters / producers from EU has filed submissions for the determination of normal value in the form and manner required by the Authority.

20. European Commission has submitted that its claim of no dumping should be treated as withdrawn and the Authority need to examine the injury aspect only irrespective of whether dumping is continuing or not. In the preceding section, it has been demonstrated that even in a partial review of continuation and likelihood of injury to the domestic industry in the event of withdrawal of duty, assessment of extent of dumping is a vital component of the determination. The domestic industry has argued that the applicant has not cooperated in these proceedings as required by law and only provided limited arguments on injury and causal link without evidence and conveniently chosen not to provide any information pertaining to their normal value. This is contrary to the law and settled jurisprudence. Therefore, in the absence of any other information, the information provided by the domestic industry has been considered as the basis of normal value for the purpose of assessment of extent of current dumping. The domestic industry has submitted that it made best efforts to procure evidence of the domestic prices prevailing in the E.U but could not procure prices for the period of investigation.

21. Article 6.8 of the Agreement provide that in case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Annex II to the Agreement further provides that such determination can even be made on the basis of information provided by the domestic industry. Since none of the exporters / producers from EU has filed the required information for determination of normal value, the normal value for all exporters / producers has been constructed based on facts available as per Rule 6(8) of AD Rules. The normal value is therefore, constructed as US\$****/Kg. for all exporters / producers from EU.

EXPORT PRICE:

22. The export price is determined on the basis of import statistics provided by DGCI&S. As per DGCI&S import statistics EU has exported 764 MT of IAS during the POI. To arrive at ex-factory export price, adjustments have been considered as provided by the domestic industry. The ex-factory export price is determined as US\$****/Kg. for all exporters / producers from EU.

E.2 USA

NORMAL VALUE

23. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975. None of the exporters / producers from USA has filed submissions in the form and manner required by the Authority. Article 6.8 of the Agreement provides that in cases any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Annex II to the Agreement further provides that such determination can even be made on the basis of information provided by the domestic industry. Since none of the exporters / producers from USA has filed the submissions for determination of normal value, the normal value for all exporters / producers has been constructed based on facts available as per Rule 6(8) of AD Rules. In absence of any other information, the information provided by the domestic industry has been considered as the basis of normal value for the purpose of assessment of extent of current dumping. The domestic industry has submitted that it made best efforts to procure evidence of the domestic prices prevailing in the E.U but could not procure prices for the period of investigation. The normal value is therefore, constructed as US\$****/Kg. for all exporters / producers from USA.

EXPORT PRICE:

24. The export price is determined on the basis of import statistics provided by DGCI&S. As per DGCI&S import statistics USA has exported 1108 MT of HAS during the POI. To arrive at ex-factory export price, adjustments have been considered as provided by the domestic industry. The ex-factory export price is determined as US\$****/Kg. for all exporters / producers from USA.

E.3 JAPAN

NORMAL VALUE

25. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975. None of the exporters / producers from Japan has filed submissions in the form and manner required by the Authority. Article 6.8 of the Agreement provides that in cases any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Annex II to the Agreement further provides that such determination can even be made on the basis of information provided by the domestic industry. Since none of the exporters / producers from Japan has filed the submissions for determination of normal value, the normal value for all exporters / producers has been constructed based on facts available as per Rule 6(8) of AD Rules. In absence of any other information, the information provided by the domestic industry has been considered as the basis of normal value for the purpose of assessment of extent of current dumping. The domestic industry has submitted that it made best efforts to procure evidence of the

domestic prices prevailing in the E.U but could not procure prices for the period of investigation. The normal value is therefore, constructed as US\$****/Kg. for all exporters / producers from Japan.

EXPORT PRICE:

26. With response to the disclosure statement the domestic industry has argued that the determination of dumping margin in respect of Japan is determined negative due to incorrect import transactions reported by DGCI&S. The Authority has examined the transaction wise data during the POI received from DGCI&S, Kolkata and the same has been considered for determination of weighted average export price in absence of non-cooperation of the exporters / producers from Japan. As per DGCI&S import statistics Japan has exported 704 MT of IAS during the POI. To arrive at ex-factory export price, adjustments have been considered as provided by the domestic industry. The ex-factory export price is determined as US\$****/Kg. for all exporters / producers from Japan. Based on the normal value and export price determined for the exporters/producers from Japan, the dumping margin is found negative as export price was more than normal value during the POI. Therefore, Japan has been excluded from the subject countries in this investigation and their volume of imports has been segregated from dumped imports for the purpose of injury examination. In view of the above, Japan have been excluded from the subject countries in this investigation. Henceforth, only EC and USA shall constitute as subject countries in this investigation wherever it is referred.

DUMPING MARGIN

27. It is noted that because of the typing mistake the dumping margin percentage were wrongly typed in the disclosure statement which has been corrected now. Based on the normal value and export price as determined above, the Authority determined the dumping margin as under:

SUBJECT COUNTRIES	NORMAL VALUE(\$/MT)	EXPORT PRICE(\$/MT)	DUMPING MARGIN (%)
EC	****	****	37.16
USA	****	****	14.58
JAPAN	****	****	-ve

28. In view of the above, Japan have been excluded from the subject countries in this investigation. Henceforth, only EC and USA shall constitute as subject countries in this investigation wherever it is referred. The Dumping Margin determined for the subject countries have been found to be significant.

METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

F. INJURY DETERMINATION

F.1 CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY

29. As per annexure-II (iii) of Anti Dumping Rules, in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping

investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject countries is more than 2%. The volume of imports from these subject countries collectively are 45.82% and individually it was more than 3% of the total imports.

30. On examination of information, the Authority found that the subject goods coming from subject countries have been imported under the same tariff classification. The user industry for the imported product and the domestic products were the same. Same product has been sourced from different countries by users and used interchangeably. The channels of imports are also found to be similar. The Authority has, therefore, found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article in the light of conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and like domestic product. The Authority has considered to examine cumulatively the effect of injury by imports of subject goods from subject countries on the domestic industry.

F.2 CONTINUATION OF INJURY

F.2.1 VIEWS OF THE APPLICATIONS

31. The applicant has submitted that the domestic industry has improved its performance and does not suffer any material injury. They have further submitted that the domestic industry which is represented by sole producer M/s Deepak Nitrite Ltd. has improved its profitability and not undercutting the domestic sales prices of the domestic industry. Therefore, there is no likelihood of re-occurrence of injury to the domestic industry on export from EC. Therefore, there is no basis to allege that injury has been caused due to the imports from EU and therefore there is absence of causal link.

F.2.2 VIEWS OF IMPORTER

32. Views of M/s. Virchow Laboratories are summarized below

i) Virchow Laboratories Limited, Hyderabad (Hereinafter referred to as Virchow Lab) has supported the application for the request for review by the European Commission on behalf of the EU exporters in the matter of Anti Dumping Duty imposed on the imports of Hydroxyl Amine Sulphate (HAS) originating in or exported from EU, USA and Japan.

ii) Virchow Laboratories Ltd., is the largest producer of Sulfamethoxazole in the world with an output of 4800 MT per annum. HAS is an important raw material that it utilized in the manufacture of Sulfamethoxazole.

iii) They have submitted that they have not bought HAS from the domestic industry. The product that is manufactured by the domestic industry is significantly inferior in terms of quality. In fact it is submitted that they have continued to import the product under investigation, and have paid the anti dumping duty on the product instead of buying it from domestic industry due to quality differences.

iv) The prices that have been offered by the domestic industry are at a lower price than the landed cost of the imported product after the imposition of the anti dumping duties. The prices that have been offered by the domestic industry are far lower than the price of the product that is available for sale after the imposition of the anti dumping duties. The imposition of the anti-dumping duty has not served to benefit the domestic industry in any manner. It is submitted that there were a number of units that were present in India which imported the product under consideration to manufacture the end product of SMX/SMZ or other drugs were forced to shut down due to the non viability of the HAS industry.

v) The domestic industry has offered to sell the said material end users at a price in the range of Rs. 55/- to Rs. 60/-. This price band is significantly lower than the price of the product that would be available after the imposition of the anti-dumping duty, which would be in the range of Rs. 80/- to Rs. 85/-, even the material imported under advance license, the landed value of the same is higher or in the same region as offered by the domestic industry.

vi) Domestic industry is selling the material in the domestic market at far lower prices than the reference price and the current cost of production of the domestic industry is lower than the reference price already fixed. as the landed value of imported material is above the current non-injurious price hence, no price undercutting and price suppression has occurred.

vii) They have submitted that anti-dumping duty has not helped of the domestic industry, stating that all the injury parameters of the domestic industry have improved because of the imposition of the anti dumping duty. The domestic industry has claimed that in the initial two years after the imposition of the anti-dumping duties, there was an improvement on all parameters of the domestic industry, however, during the current period of investigation, the production sales, selling price and profits have come down. The contention of the domestic industry that the anti-dumping duty has helped the domestic industry improve on all injury parameters, then there are no reasons as to why during the period of investigation, the performance of the domestic industry has come down. This clearly implies that there are some other factors causing injury to the domestic industry. The demand of HAS in the country is about 7000 MT. The capacity of the domestic industry to product HAS is about 1,500 MT. The clear market for domestic industry is about 2000 MT (excluding SMX demand). Even after the imposition of anti-dumping duty, if the domestic industry is not able to achieve its capacity utilization upto 100%, there must be some other reasons apart from dumping.

viii) The likelihood of recurrence of injury is not possible as the SMX producer were never the customer of domestic industry and in the near future also it does not seem that SMX producers can be catered by the domestic industry because of quality and capacity. Hence, the quantum of imports will remain unchanged until unless the demand of HAS come down.

F.2.3 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

33. Views of Domestic industry are summarized below:

i) Domestic industry has submitted that there are no direct exports for end use except against Advance License Scheme by M/s. BASF to India since the imposition of the anti-dumping duty. They have further submitted that imposition of anti-dumping duty enabled the domestic industry to improve its profitability, cash flow and increase its market share in relation to demand. Even though performance of the domestic industry was not satisfactory, domestic industry submits that this can not become a ground for premature revocation of present duty. Domestic industry could not improve further because producers in other countries have resorted to dumping of subject goods. Further, the consumers are taking undue advantage of the Advance License provisions and are resorting to imports beyond what is consumed in the ultimate product. In fact, market share of the domestic industry has increased. Further, while it is true that the product is being dumped from Belarus, domestic industry submits that this can not become ground for revocation of present duty.

ii) They have submitted that domestic sales has increased upto the year 2001-2002 and declined thereafter in 2002-2003 and slightly increased during the POI. The domestic industry has submitted that increase in sales volumes during the POI is due to reduction in the selling price of the subject goods. Even the production and capacity utilization of the domestic industry has declined during the POI due to continued dumping of subject goods from subject countries. The capacity utilization has declined from 76% during the 2001-2002 to 61% during the POI.

iii) The domestic industry posted a profit upto 2002-2003 after recovering from a situation of financial loss. However it has once again suffered financial loss during the POI primarily due to reduction in the selling price of the subject goods. They have submitted that the costs of production of the subject goods has marginally declined, whereas selling price has declined far more than the decline in cost of production of the subject goods, force the industry to suffer financial loss.

iv) Cash flow situation from the operating activities improved in 2002-2003 but declined in the period of investigation. Similarly return on investment which was -19% in the year 2000-2001 and improved during 2001-2002 and 2002-2003, before becoming negative in the POI.

v) Once again the productivity per employee has declined due to decline in production inspite of reduction in level of employment. The domestic industry with an effort to improve its productivity and financial health reduced the number of employees at its Vadodara plant which have had an impact on the subject goods. They have also submitted that inspite of reduction in wages during the POI the profits of the domestic industry declined.

vi) The market share of the domestic industry has improved over the years when the market share of subject countries declined which shows that the domestic industry has improved its position due to existing anti-dumping measures. The domestic industry has argued that despite decline in domestic demand, share of the subject countries remained

more than 50% in term of total demand. Despite decline in demand, the market share of the domestic industry remained significant and rather increased. They have submitted that possible discontinuance of anti-dumping duty at this pre-mature stage would again result in loss of market share of the domestic industry.

- vii) The landed value of imports from subject countries are significantly below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry which is resulting into severe price underselling. Even the imports from the subject countries are severely undercutting the prices of the domestic industry as the landed value of the subject goods are much below the domestic selling price.
- viii) The average stocks of the subject goods with the domestic industry have been increasing over the period. The growth of the domestic industry has been positive on a number of parameters upto 2002-2003 which has become negative during the POI. In this scenario they have submitted that they could not make additional investments in the HAS plant in order to face competition with the dumped imports.
- ix) In general the performance of the domestic industry improved between 2000-2001 and 2002-2003 but deteriorated once again in the POI and they have submitted that this deterioration is due to presence of dumped imports.
- x) The domestic industry has submitted that they have suffered with continued material injury from the dumped imports from subject countries and possible discontinuance of duty would result in further injury to the domestic industry as dumped imports will find the access in the domestic market. They have further stated that changed situation in the POI compared to the preceding years that the domestic industry is vulnerable to injury if the measures were allowed to be removed or curtailed.
- xi) The market share of imports is significant the decline in market share during the injury period is due to the imposition of anti-dumping duty and imports were mostly under the duty exemption scheme.
- xii) The dumping margin from subject countries are more than the prescribed limits and are significantly higher. In the original investigation also dumping margin was significant.
- xiii) The domestic industry submits that the injury to the domestic industry in the POI was caused by the dumped imports from the subject countries and if the anti-dumping duties are removed the anti-dumping duty will intensify the duty to the domestic industry.
- xiv) The domestic industry has submitted that the imports from Belarus are also causing injury to the domestic industry as these imports are also coming at the dumped prices. The volume and value of imports from other sources are de-minimis.
- xv) The demand of the domestic industry showing a decline during the POI. The domestic industry submits that the imports are mostly coming under the duty exemption scheme, if these imports are considered then the demand will show a progressive increase.

xvi) The domestic industry is the sole producer of the subject goods in India, therefore trade restricted practices or conditions of competitions between the domestic producers cannot be a possible cause of injury.

xvii) With response to the disclosure statement the domestic industry has submitted that the contention of EC that injury investigation under the changed circumstances review is a stand along investigation, without examination of dumping, does not appear to be appropriate. The Designated Authority has correctly examined both the dumping and injury determination as per the obligation under WTO Agreement.

F.2.4 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

34. Rule 11 and Annexure II of the AD Rules requires the Authority to objectively examine the volume of dumped imports and the effect of dumped imports in the domestic market for like article and the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products. Since the imports from the subject countries/ territories have been treated as dumped imports, the Authority proposes to examine the volume and price effect of these dumped imports on the domestic industry and also analyse the injury parameters to determine whether the domestic industry is continuing to suffer material injury on account of such dumped imports.

VOLUME OF IMPORT AND IMPORT PRICES:

35. DGCI&S data for the injury analysis period shows that imports have taken place from several sources including the subject countries/territories during the injury investigation period. Accordingly, the import as reported by DGCI&S are as follows:

MT	2000-2001	2001-2002	2002-2003	POI
EU	2288	1394	1086	764
USA	617	549	361	111
Subject countries	2905	1943	1447	875
Other countries	1018	1634	1631	1035
Total imports	3923	3578	3078	1910
Share in imports				
Subject countries	74.05	54.32	47.02	45.82
Other countries	25.95	45.68	52.98	54.18

36. The above data shows that total volume of imports has declined in absolute nos from 3923 MT during 2000-2001 to 1910 MT during the POI whereas the imports from other countries has increased from 1018 MT during 2000-2001 to 1035 MT during the POI. It is noted that the share of imports in total imports from the subject countries in total imports has decreased from 74.05% in 2000-2001 to 45.82% during the period of investigation and the share of imports in total imports from other countries has increased from 25.95% during 2000-2001 to 54.18% during the period of investigation. As regards the prices, it has increased from Rs. 37248/MT during 2000-2001 to Rs. 42889/MT during the POI.

CAPACITY, OUTPUT AND CAPACITY UTILIZATION OF DOMESTIC INDUSTRY

37. The performance of the domestic industry has also been examined with reference to its capacity, output and capacity utilization and impact of the dumped imports on these parameters, if any. The production of the domestic industry has declined from 1180 MT during 2000 -2001 to 952 MT during the POI. The production capacity of the domestic industry has remained the same during the injury period and the capacity utilisation has declined during the POI in the declining demand scenario during the POI.

Year	Installed capacity (MT)	Production (All Products) (MT)	Capacity Utilization (%)
2000-01	1560	1180	76
2001-02	1560	1178	76
2002-03	1560	1035	66
2003-04	1560	952	61

DEMAND AND MARKET SHARES

38. The total demand has been estimated based on the combined volume of domestic sales and imports from other countries, as well as imports made into the domestic market from the Subject countries.

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	POI
Demand(MT)				
Domestic sales	1018	1183	850	923
Imports from subject countries	2905	1943	1447	875
Imports from other countries	1018	1634	1631	1035
Total imports	3923	3578	3078	1910
Total demand	4942	4760	3928	2833
Market share(%)				
Domestic industries	21	25	22	33
Subject countries	59	41	37	30
Other countries	20	34	41	37

39. The demand of the subject goods has decreased significantly from 4942 MT during 2000-2001 to 2833 MT during the POI. At the same time imports have also declined both in absolute numbers and in terms of market share. The market share of domestic industry has increased from 21% during 2000-2001 to 33% during POI whereas market share of dumped imports from subject countries has showing a trend of decline and it has declined by 29% during the POI. However, imports from non dumped sources have increased by 17% in total demand. Therefore, the data indicates that after imposition of duty the condition of the domestic industry has substantially improved in terms of its

market share and there is no volume effect of the dumped imports to the domestic industry.

SALES REALISATION OF THE DOMESTIC INDUSTRY

40. The selling price of the domestic industry has reduced from 100 during 2000-2001 to 81 during the POI signifying a reduction of 19 % from 2000-2001 levels. There is also a significant reduction in the cost of production also during previous three years. The cost of production and net selling prices of the domestic industry as per the record maintained by it has been as follows:

Year	Cost to make & sell Per MT (Rs.)	Selling Price / MT (Rs.)	Indexed data
			Profit / (Loss) per MT (Rs.)
2000-2001	****	****	****
2001-2002	****	****	****
2002-2003	****	****	****
2003-2004	****	****	****

41. It is noticed that there is a significant reduction in the cost of production from 100 during 2000-2001 to 76 during the POI and the corresponding decline in selling prices is of 19%. However, the drop in cost of production is much more compared to the selling prices of the domestic industry. The domestic industry from a loss of -100 during 2000-2001 has improved its financial position during the injury period and reflecting a profit to the extent of 764 during the POI. The profit per MT of the product after showing significant improvement after imposition of the duty but has shown a decline between 2002-03 and 2003-04.

PRICE UNDERCUTTING

42. A comparison for subject goods during the period under investigation was made between the weighted average landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. The landed value of imports from the subject countries was lower than the net sales realization of the domestic industry for the subject goods during the POI thereby, undercutting the selling price of the domestic industry. The undercutting margin was in the range of 7% to 16% during the POI.

<i>Price Undercutting</i>	<i>EC</i>	<i>USA</i>	<i>Subject Countries</i>
Net sales realization	****	****	****
Landed Value	52724	63114	54040
Price Undercutting	****	****	****
Price Undercutting (%)	****	****	****

PRICE UNDERSELLING

43. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producer by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. Also in order to eliminate inefficiencies, the capacity utilization has been normated. The analysis shows that the weighted average landed value of the subject goods from subject countries is less than the non injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. The underselling margin was in the range of 5% to 15% during the POI.

Price Underselling	EC	USA	Subject Countries
Non Injurious Price	****	****	****
Landed Value	52724	63114	54040
Price Underselling	****	****	****
Price Underselling (%)	****	****	****

44. Further, the landed value of subject goods is lower than the domestic selling price of the domestic industry thereby, undercutting the domestic sales prices. However, it is noted that the domestic selling price is higher than the non injurious price determined for the domestic industry.

OTHER INJURY PARAMETERS

45. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed here as follows:

PROFITABILITY

46. The profitability of the domestic industry has been analysed from the record of the company:

Year	Cost to make & sell Per MT (Rs.)	Selling Price / MT (Rs.)	Indexed data
			Profit / (Loss) per MT (Rs.)
2000-2001	****	****	****
2001-2002	****	****	****
2002-2003	****	****	****
2003-2004	****	****	****

47. The domestic industry's profitability has improved from -100 during 2001-2001 to 764 during the POI. It has certainly declined during the POI if compared with the immediate preceding years, however from a loss scenario of the domestic industry during the base year has entered into the profit. It can be seen from the above table that the profits of the domestic industry have improved during the POI.

EMPLOYMENT

48. The domestic industry has curtailed the number of employees as its production has dropped from 100 during 2000-2001 to 81 during the POI. But the productivity per employee have just dropped above 2%, therefore it can not be the cause of injury to the domestic industry. The domestic industry has claimed that the number of employees have been reduced as a cost cutting measure to improve the productivity. It is noted that change in level of employment has not caused any injury to the domestic industry.

Year	No. of Employees	Production (Kg)	Productivity Per Employee (Kg)
2000-2001	100	100	100
2001-2002	121	100	82.30
2002-2003	90	88	97.50
2003-2004 (Period of Investigation)	83	81	97.68

WAGES

49. The wages for the subject goods has increased from 100 during 2000-2001 to 122 during the POI, at the same time wages as percentage of sales has also shown a increase from 100 during 2000-2001 to 130.25 during the POI. The Wages and salary per employee of the domestic industry has increased during the period of investigation. However, it is observed that the domestic industry is earning a reasonable profit even after the increase in wages of the domestic industry. As such wages could not be a factor for injury to the domestic industry.

Year	Wages per MT	Wages as % of sales	Wages per employee
2000-2001	100	100	100
2001-2002	96	84.94	79
2002-2003	115	125.27	112
2003-2004 (Period of Investigation)	122	130.25	119

PRODUCTIVITY

50. There is a marginal drop in productivity in terms of production per employee due to drop in output during this period. Productivity of the domestic industry, as reflected in

terms of production per employee, has a drop of 2% during the POI whereas the production has dropped from 100 to 81 in the same period. It can not, therefore, be said that the domestic industry has suffered injury due to decline in productivity.

Year	No. of Employees	Production (Kg)	Indexed
			Productivity Per Employee (Kg)
2000-2001	100	100	100
2001-2002	121	100	82.30
2002-2003	90	88	97.50
2003-2004 (Period of Investigation)	83	81	97.68

INVENTORIES

51. Inventory position of the Company shows significant improvement. The stocks of the domestic industry decreased from 100 during 2000-2001 to 16.31 during the POI and as a percentage of sales it has decreased from 100 during 2000-2001 to 16.31 during the POI.

Year	As a % of month sales	Indexed
		Closing Stock MT
2000-2001	100	100
2001-2002	4.44	5.15
2002-2003	136.17	113
2003-2004	18.01	16.31

INVESTMENT AND RETURN ON INVESTMENT

52. There has been no capacity addition or any marakable fresh investment by the applicants during the investigation period. The domestic industry has been consistently improving its profitability. The domestic industry has achieved a positive ROCE during the POI from a negative return in the base year.

Year	Indexed
2000-2001	-100
2001-2002	91
2002-2003	154
POI	49

CASHFLOW

53. The domestic industry is a multi-product company with multiple production plants, it could not be possible to determine the actual magnitude of cash-flow of the product. However it has been observed that the company has improved its cash-profit of the product substantially over the period of injury.

MAGNITUDE OF DUMPING

54. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that the dumping margin determined for the subject countries during the POI, is substantial, even when the antidumping duty is in force.

FACTORS AFFECTING PRICES

55. Change in cost structure if any, competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. There is no viable substitute to this product and M/s Deepak Nitrite is the sole producer of the subject good in India. Therefore, domestic competition does not affect the prices.

EVIDENCE OF LOST CONTRACTS

56. The domestic industry did not produce any evidence regarding loss of order or contract due to imports of subject goods from subject countries. As such loss of contract could not be a factor for injury to the domestic industry.

CONCLUSION

57. On the basis of examination of injury factors, it is noted that the market share of the domestic industry in total demand has increased whereas the market share of dumped imports from subject countries has gone down. The total imports of subject goods has decreased roughly by 50% during the POI compared to the base year whereas the production and the domestic sales of the domestic industry has not declined in proportion to the decline in total demand of the subject goods. The profitability of domestic industry has improved during the POI. The cash profit of the domestic industry has also improved during the injury period. The inventory position of the domestic industry is also showing a growth during the POI and as a percentage of month's sales it has also improved. The dumped imports from subject countries are undercutting the selling price of the domestic industry but the domestic industry is realizing the selling price more than the non injurious price determined for the domestic industry.

F.3 OTHERS KNOWN FACTORS

Volume and prices of imports from other sources

MT	2000-2001	2001-2002	2002-2003	POI
Subject countries	2905	1943	1447	875
Other countries	1018	1634	1631	1035
Total imports	3923	3578	3078	1910
Share in imports				

Subject countries	74.05	54.32	47.02	45.82
Other countries	25.95	45.68	52.98	54.18

58. During the POI, imports have taken place from many countries other than the subject countries, including Belarus. Total import from other sources has increased from 1018 MT during 2000-2001 to 1035 MT during POI, however it is noted that 356 MT alone was exported from Belarus during POI. The Authority also noted that weighted average import price from these sources is more or less same as the dumped import prices from the subject countries. Therefore, the imports from the other sources also appear to have significant effect on the domestic industry, both in terms of volume and value.

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Demand	4942	4760	3928	2833
Indexed	100	96.33	79.48	57.33

59. Total domestic demand of the product under consideration has declined from 4942MT during 2000-2001 to 2833 MT during the POI after a increase in 2001-2002 and declined subsequently in both years. The market share of domestic industry in the demand has shown a substantial increase in a decreasing demand scenario whereas the share of subject countries has decreased. At the same time share of imports from other sources has increased from 21% to 37% in total demand.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

60. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The domestic industry is the sole producer of the subject goods in the country. Moreover, imports from other sources have sizable presence in the Indian market, which has grown substantially along with the imports from subject countries.

Development of technology and export performance

61. Technology or technology related issues have not been raised by any interested party as cause of injury to the domestic industry. It is noted that the domestic industry has exported a very small quantity during the POI as a market entry move and that does not substantially affect the profitability of the company.

Productivity of the Domestic Industry

62. Productivity of the domestic industry in terms of labour output and daily output has shown a marginal decline compared to the base year. However, it is noted that this marginal decline is negligible compared with the decline in production.

F.4 LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

63. Since the Authority has already determined that the subject goods are continuing to enter the Indian market at dumped prices from the subject countries, an analysis of recurrence of dumping is not required. However, looking at the non-cooperation of the exporters to provide credible evidence on the normal value of the product in the subject countries it can be reasonably concluded that the exports would continue to enter the market at dumped prices. But looking at the price level at which the product is entering the Indian market from all sources it is unlikely that further reduction of the export prices could take place immediately.

64. Therefore, it is pertinent to examine whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed or varied. It has already been established that the landed value of imports from the subject countries without the antidumping duty is below the selling price of the domestic industry and the NIP determined by the Authority for the domestic industry. However, the Authority notes that the net sales realization of the subject goods is more than the non injurious price determined for the domestic industry. Therefore, removal of the duty fixed in terms of reference price is not likely to materially affect the domestic industry.

65. However, in addition to the examination of material injury, likelihood of recurrence of injury or threat of injury to the domestic industry has been examined by the Authority on the basis of the claims made by the domestic industry.

66. The Domestic Industry has submitted that the threat of material injury should be examined in terms of Annexure II (vii) of the Rules, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

- (a) *a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
- (b) *Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
- (c) *Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,*
- (d) *Inventories of the article being investigated."*

67. Though the above provision do not provide appropriate parameters for examination of likelihood of recurrence of injury in a review investigation, in the absence

of any express provision In this regards the Authority has examined some of these parameters to draw inference on the subject.

68. In the instant case, the imports of the subject goods have decreased over the injury period and demand has also declined to attract more imports. It is noted that the domestic industry did not substantiate with evidence in support of its apprehension of imminent injury and in absence of substantiated evidence regarding threat of injury, the Authority did not find appropriate to recommend continuation of anti-dumping measures as current imports are not causing injury to the domestic industry. There is no evidence on record to show that the injury would recur if the duties are discontinued. However, it is noted that the domestic selling price is higher than the non injurious price determined for the domestic industry.

G. CAUSAL LINK:

69. The submissions made by interested parties in respect of the issue of causal link have been examined. A detailed examination was made with regards to the issues pertaining to the material injury to the domestic industry and causal link between the material injury to the domestic industry and dumped imports. Paragraph (v) of Annexure II of the Anti-dumping Rules reads as under:

"It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the designated authority. The designated authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry."

70. It is noted that market share of the domestic industry has increased in demand during the period of investigation from 21% in 2000-01 to 33% during the period of investigation. It is noted that the net sales realisation of the subject goods of the domestic industry is above the non injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. It is noted that the dumped imports from subject countries has decreased from 74.05% during 2000-01 to 45.82% during the POI of total imports whereas imports from other sources increased from 25.95% during 2000-01 to 54.18 % during the POI. It is also found that volume and prices of imports from other sources which constitutes 54.18% may have adverse affect on domestic prices of the domestic industry.

71. The Authority is of the view that domestic industry is not suffering material injury due to dumped imports from subject countries and it may not be appropriate to continue with the existing anti dumping measures. The examination of dumping and injury indicates that there is no current injury to the domestic industry due to dumped imports and not likely to have injury due to dumped imports. The domestic industry argued that dumping is still continuing from the subject countries and causing injury to the domestic industry. The domestic industry has further submitted that withdrawal of existing anti-dumping duty may likely to lead a recurrence of dumping and injury to the domestic industry. It is noted that the domestic industry did not substantiate with evidence in support of its apprehension of imminent injury due to dumped imports from subject countries. In absence of substantiated evidence regarding threat of injury, the Authority did not find appropriate to recommend continuation of anti-dumping measures as current imports are not causing injury to the domestic industry. There is no evidence on record to show that the injury would recur if the duties are discontinued. The Authority, therefore concludes that the discontinuation of the anti dumping duty may not likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.

H. FINAL FINDINGS:

72. The Authority after considering the foregoing, concludes that:

- (a) subject goods originating in or exported from subject countries have been exported to India below their normal value, resulting in dumping;
- (b) the domestic industry has not suffered material injury due to dumped imports;
- (c) and discontinuation of anti-dumping duties on the subject goods from subject countries may not likely to lead to the recurrence of injury and dumping to the domestic industry;
- (d) In view of the above, the Designated Authority considers it appropriate to recommend discontinuation of the anti-dumping duties recommended earlier vide Notification No. 59/1/2001- DGAD dated 01/03/2001 and imposed on all imports of Hydroxyl Amine Sulphate (HAS) classified under chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 (as amended) originating in or exported from EU, USA and Japan.
- (e) An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (as amended).

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority